A Daily News Magazine
भोपाल
मंगलवार, 09 जून, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 277, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

टीएमसी को टूट से बचाने ममता बनर्जी के पास क्या हैं विकल्प?

प्रभाकर मणि तिवारी

ममता बनर्जी ने जिस पार्टी का गठन करके अपनी मेहनत के बूते उसे महज़ 13 साल के भीतर शून्य से शिखर तक पहुंचाया था, क्या वह उनके हाथों से निकल जाएगी? क्या उन पर अपने ही घर (पार्टी) में बेघर होने का ख़तरा मंडरा रहा है? पार्टी के 58 विधायकों की बग़ावत और निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी के सदन में विपक्ष का नेता बनने के बाद, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हलकों में यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता अब आगे क्या करेंगी। क्या वो जादुई पौराणिक पक्षी 'फ़ीनिक्स' की तरह एक बार फिर राख से उठकर खड़ी हो सकती हैं?

अपने चार दशक से भी ज़्यादा लंबे राजनीतिक कॅरियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक विकट हालात का सामना किया है। मिसाल के तौर पर वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का महज़ एक सीट पर जीतना हो या फिर वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में महज़ 29 सीटों तक सिमट जाना। लेकिन यह पहली बार है कि पूरी पार्टी उनके हाथों से निकलती नज़र आ रही है।

दो-तिहाई विधायकों की बग़ावत के बाद फ़ौरी क़दम उठाते हुए ममता ने पार्टी की तमाम कमेटियों और संगठनों को भंग कर दिया है और चुनावी नतीजों के गहन विश्लेषण की बात कही है। महासचिव अभिषेक बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। इस बग़ावत के बाद उन्होंने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उनको पहले से ही पार्टी में इस टूट का आभास मिल गया था।

बाग़ी विधायकों ने साफ़ कर दिया है कि उनकी नाराज़गी अभिषेक बनर्जी और पार्टी चलाने के उनके तौर-तरीक़ों से है, ममता से नहीं।

लेकिन ममता की मुश्किल यह है कि यह जानते हुए भी कि वो अभिषेक को नहीं छोड़ सकतीं। इसकी वजह भी है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं, 'यह सही है कि पार्टी में अभिषेक का कद बढ़ने के साथ ही कई पुराने नेताओं की नाराज़गी बढ़ने लगी थी। 'उनके अलावा, नई पीढ़ी के कई नेताओं में भी असंतोष बढ़ रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने भी इसी वजह से पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। सब कुछ जानते हुए ममता, अभिषेक को नहीं छोड़ सकतीं। अभिषेक को छोड़ने या उनके खिलाफ़ किसी कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि वो बाग़ियों की धमकी के आगे झुक गई हैं। झुकना ममता के स्वभाव में नहीं है।'

तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि 'बदली हुई परिस्थिति में ममता बनर्जी, विधानसभा की घटना की क़ानूनी वैधता को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रही हैं। इसके लिए विधि विशेषज्ञों से भी सलाह ली जा रही है। पार्टी अदालत में सवाल उठाएगी कि पार्टी से निकाले गए किसी विधायक को विधानसभा में उसी पार्टी का नेता कैसे बनाया जा सकता है?'

तृणमूल कांग्रेस सांसद और एडवोकेट कल्याण बनर्जी कहते हैं, 'असली तृणमूल कांग्रेस से टूटकर बना गुट, जिसे विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला है, अवैध है। ऋतब्रत को पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था। जो पार्टी का सदस्य ही नहीं है वो तृणमूल कांग्रेस की ओर से विपक्ष का नेता कैसे बन सकता है?' बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष ने जो किया है, देश में उसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो नेता पार्टी में ही नहीं है, उसे विपक्ष का नेता बना दिया गया है। पार्टी इस मामले को क़ानूनी चुनौती देगी।'

पार्टी अब अपने सांसदों की गतिविधियों पर भी निगाह रख रही है। ख़ासकर हाल में चार बार की सांसद रही काकोली घोष दस्तीदार के बग़ावती रुख़ के बाद पार्टी में यह आशंका बढ़ रही है कि कहीं उसके सांसदों का हाल भी आम आदमी पार्टी के सांसदों की तरह न हो। दूसरी ओर, बंगाल में सत्ता और उसके बाद पार्टी के भी लगभग हाथ से निकलने के बाद ममता ने अब दिल्ली की ओर ध्यान केंद्रित किया है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता बताते हैं, 'मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी के पहले दिल्ली दौरे के दौरान ही वहां बंग भवन में ऋतब्रत बनर्जी ने उनसे मुलाक़ात की थी। पार्टी में बग़ावत के बीज उसी दिन पड़ गए थे।' हालांकि बीजेपी के नेता इस बारे में इनकार करते रहे हैं।

प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य कहते हैं, 'यह तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इससे बीजेपी का कोई लेना-देना नहीं है।' तृणमूल कांग्रेस मौजूदा परिस्थिति के लिए बीजेपी के बंगाल मॉडल को ज़िम्मेदार ठहरा रही है। इंडिया गठबंधन की उसकी सहयोगी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर उससे सहमत है। इन दोनों दलों का कहना है कि परदे के पीछे बीजेपी का समर्थन नहीं होने पर ऋतब्रत को न तो बग़ावत का साहस होता और न ही उनको इतने विधायकों का समर्थन मिलता। इमेज तृणमूल कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि वर्ष 1984 के बाद बीच के दो साल छोड़ दिए जाएं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ममता सांसद या विधायक न रही हों। फ़िलहाल उनके लोकसभा या विधानसभा में पहुंचने का कोई मौक़ा नज़र नहीं आ रहा है। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम कहते हैं, 'ममता बनर्जी ने ही बंगाल में वाममोर्चा से मुक़ाबले के लिए बीजेपी को पांव जमाने में मदद की थी। अब उनको इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ रहा है।' ममता के कट्टर आलोचक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कहते हैं, 'ये ममता बनर्जी ही थीं, जिन्होंने किसी दौर में कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। अब इतिहास ख़ुद को दोहरा रहा है।'

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता अपने लंबे राजनीतिक कॅरियर में पहले भी कई प्रतिकूल हालात से गुज़री हैं, और कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस बार उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हैं। वरिष्ठ पत्रकार पुलकेश घोष कहते हैं, 'चुनावी नतीजों से साफ़ है कि अब न तो ममता के पास वैसा समर्थन रहा है और न ही वैसे ज़्यादा नेता ही रहे हैं। इस बग़ावत से उपजी चुनौती से पार पाना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है।' वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक मोनिदीपा बनर्जी कहती हैं, ऐऐसंभवतः यह ममता के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दौर है। उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिख रहा है।अब उन्हें यह साबित करना होगा कि उनमें अभी भी चिंगारी बाक़ी है।'

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

'दीदी' के हाथ से अब 'दिल्ली' भी निकली

● बंगाल के बाद बड़ा 'खेला', बागी हुए 20 सांसद ● लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर मांगी अलग मान्यता

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कन्फर्म हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है। सांसदों ने अपने पत्र में बताया है कि वह एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। हस्ताक्षर करने वालों में अरुप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी रॉय, जगदीश वसुनिया, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन, शर्मिला सरकार, जून मालिया, वापी हलदर, असित मल, सुवेंदु शेखर रॉय समेत 20 सांसद बताए जा रहे हैं। बागी गुट की नेता के तौर काकोली घोष दस्तीदार को मान्यता देने की मांग की गई है।

सांसदों ने मीटिंग के बाद बनाया गुट- लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट की मान्यता देने की चिट्ठी लिखने से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बागियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय भी शामिल थे। बाद में सुखेंदु शेखर रॉय ने सभापति सी. पी. राधाकृष्णन से मुलाकात कर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और टीएमसी छोड़ने की घोषणा की। उन्होंने

बताया कि मैंने पार्टी से इस्तीफा देने के अपने फैसले से ममता बनर्जी को व्हाट्सऐप और ईमेल के जरिये अवगत करा दिया है। विधानसभा में विधायक दल में टूट पर हो रहे दावों पर सुखेंदु रॉय ने कहा कि क्या कोई यह बता सकता है कि राज्यसभा या लोकसभा में वैसी ही स्थिति पैदा नहीं होगी।

ममता बनर्जी की घट गई ताकत- बता दें कि तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल में बगावत उस समय हुई है, जब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बीजेपी के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे थे। टीएमसी सांसदों में संभावित बगावत को रोकने के लिए पहले अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद शनिवार शाम को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी, लेकिन टीएमसी सांसदों की टूट को नेतृत्व नहीं रोक पाया। विधायकों के बाद सांसदों के अलग गुट बना लेने से ममता बनर्जी की टीएमसी को तगड़ा झटका लगा है। वे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे वाली स्थिति में आ गई हैं।

सुखेंदु का दावा-टीएमसी के लोग से ममता से नाराज

टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। त्यागपत्र में उन्होंने ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार का नतीजा बताया और भाजपा की तारीफ की थी। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सुखेंदु शेखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सुखेंदु ने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा था कि पार्टी के कई लोग ममता मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थीं, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर की राज्यसभा सीट पश्चिम बंगाल से है और उनका कार्यकाल 2029 तक था। सीट खाली हो चुकी है, अब इस पर उपचुनाव कराया जा सकता है।

टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने सोमवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर के पास से हुई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता पुलिस स्टेशन में खान के खिलाफ 7 एफआईआर की गई थीं। वह नेपाल भागने की फिराक में था। अभी बंगाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस जहांगीर को कोलकाता ला रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जहांगीर को अवैध वसूली करने के आरोप में पकड़ा गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह दावा किया गया था कि जहांगीर के समर्थकों ने महिलाओं को गैंगरेप की धमकी दी थी। इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है। जहांगीर ने 2026 का विधानसभा चुनाव फालता सीट से लड़ा था।

सुप्रभात

भुलाकर दोस्ती मेरी उसे
भी कुछ तो ग़म होगा
बुरा मुझको कहेगा तो,
मगर लहजा नरम होगा
बुराई लाख लेकिन उसमें
इक अच्छाई भी तो है
डुबोता है वहीं लाकर
जहां पर पानी कम होगा
बड़ा मुश्किल हुआ होगा
उसे मेरे बिना चलना
कि तन्हाई में जब उसने
रखा पहला कदम होगा
मैं अब समझा कि मेरे
दोस्त ने मुड़ मुड़ के क्यों देखा
उसे आखिर तक मेरे
बुलाने का भरम होगा
इसी उम्मीद में तोड़ी
नहीं है दोस्ती हमने
कभी तो आपकी आँखों का
इक कोना भी नम होगा।

– राम गोपाल भारतीय

मध्यप्रदेश की उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रभावित होकर कंपनी ने भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चुना पीथमपुर को

भारत बन रहा ग्लोबल फार्मा हब, इसमें म.प्र. की बड़ी भूमिका : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया में 'फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना चुका है। वर्तमान में दुनिया भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद उत्पादन केंद्र, वैश्विक सप्लाई चेन पार्टनर और आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत को 'ग्लोबल फार्मा हब' बनाने में मध्यप्रदेश की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। मध्यप्रदेश आज हर क्षेत्र में निवेश के नये युग में प्रवेश कर आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का नया अध्याय लिख रहा है। हेलियन कंपनी ने भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मध्यप्रदेश के पीथमपुर को चुना है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की भूमि सफलता की धरती भी है। मध्यप्रदेश सरकार और हेलियन कंपनी के बीच आज परस्पर विश्वास की और असीम संभावनाओं की नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी औद्योगिक नीतियों के कारण देश-दुनिया सभी मध्यप्रदेश पर भरोसा कर रहे है। सबका यही विश्वास ही हमारी पूंजी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पीथमपुर में

स्थापित होने जा रही हेलियन ग्रुप की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के भूमि-पूजन समारोह (वर्चुअल ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रिमोट का बटन दबाकर कंपनी की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सांकेतिक भूमि-पूजन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह नए दौर का मध्यप्रदेश है। हमारा प्रदेश अब आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के इच्छुक सभी निवेशकों को उद्योग स्थापना से लेकर उत्पादन प्रारंभ होने तक हर स्तर पर राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। बताया गया कि हेलियन ग्रुप की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कंपनी द्वारा इस प्लांट में 30 प्रतिशत तक महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखने की सराहना करते हुए कहा कि यह हमारी सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और भी मजबूती देगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस ऐतिहासिक भूमि-पूजन अवसर पर हेलियन ग्रुप को बधाई देते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर आपके सहयोग के लिए साथ खड़ी है। कंपनी ने मध्यप्रदेश में तात्कालिक तौर पर 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी की मध्यप्रदेश में निवेश राशि 2 हजार करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हेलियन कंपनी सहित अन्य निवेशकों का मध्यप्रदेश में स्वागत करते हुए उन्हें बिना किसी संकोच के खुले हृदय से म.प्र. में निवेश के लिए आमंत्रित किया।

मणिपुर के उखरुल में असम राइफल्स का विरोध

● बंकर तोड़ा, झड़प में 22 तंगखुल महिलाएं घायल ● जवानों का दावा-महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला

उखरुल (एजेंसी)। मणिपुर के उखरुल जिले के शोक्वाओ और न्यू हेवन इलाके में रविवार सुबह सैकड़ों महिलाएं असम राइफल्स के जवानों और वाहनों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गईं।

मशालें, लाठियां लिए ये तंग्खुल नगा महिलाएं जवानों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं। सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी। इसके बावजूद वे डटी रहीं और 'हमारी जमीन, हमारा अधिकार' नारे लगाती रहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जवानों ने पुलिस

और मजिस्ट्रेट की गैरमौजूदगी में कई राउंड हवाई फायर किए और लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं से धक्का-मुक्की भी की गई। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में जवानों ने यह दावा किया है कि विरोध कर रही महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स में एक प्रदर्शनकारी के पैर पर गोली लगने का दावा किया गया। वहीं, 22 महिलाएं घायल हो गईं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शोक्वाओ गांव की महिलाओं ने न्यू हेवन की ओर बढ़ रहे काफिले को शनिवार देर रात ही रोक लिया था। इससे रातभर तनाव रहा। सुबह होते ही एक समूह ने शोक्वाओ पर ब्लॉकेड बनाया, तो दूसरे ने न्यू हेवन में सुरक्षा बल का बंकर ध्वस्त कर दिया।

सीआरपीएफ डीजी बोले- सरकार ने इतने हथियार किसलिए दिए

सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने मणिपुर में तैनात जवानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नागरिक इलाकों में सक्रिय सशस्त्र मिलिटेंट्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें। गौरतलब है कि दो कोबरा बटालियन यहां जल्द आने वाली हैं। तंगखुल उत्तर-पूर्व भारत के प्रमुख नगा समुदायों में से एक हैं। वे मुख्य रूप से मणिपुर के उखरुल और कामजोंग जिलों में रहते हैं। उनकी आबादी का एक हिस्सा म्यांमार के सोमरा क्षेत्र में भी बसता है।

एलएनजी संकट में भारत का संकटमोचन बना कोयला

इस तरकीब से बचाए 28000 करोड़, कभी कहा था डर्टी फ्यूल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोयला... एक ऐसी चीज जिसका इंडस्ट्री ने ईंधन के रूप में इस्तेमाल काफी हद तक बंद कर दिया था, आज फिर से संकटमोचन बनकर उभरा है। ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण होर्मुज पर नाकाबंदी के चलते भारत को ईंधन आयात में काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और एलएनजी काफी कम मात्रा में आने से इंडस्ट्री भी संकट में है। इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने

फिर से कोयले के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। कोयला लंबे समय तक डर्टी फ्यूल यानी प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन माना जाता रहा है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20°c न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 09 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 का पोस्टर सौ से अधिक स्थानों पर हुआ लोकार्पित

• भारत सहित 70 से अधिक देशों में होगा आयोजन

भोपाल। हिंदी भाषा के वैश्विक प्रचार-प्रसार और नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के उद्देश्य से विश्व रंग फाउंडेशन (भारत) एवं रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 सितम्बर (हिंदी दिवस) से 30 सितम्बर (अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस) तक भारत सहित विश्व के 70 से अधिक देशों में आयोजित होगा।

उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष आयोजित विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 में भारत सहित विश्व के कई देशों के लाखों विद्यार्थियों और प्रतिभागियों ने भागीदारी कर अभूतपूर्व रूप से सफल बनाया था। हिंदी ओलंपियाड के देश-विदेश के विजेताओं को भोपाल में आयोजित विश्व रंग महोत्सव में मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति श्री पृथ्विराज सिंह रूपेण, भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', विश्व रंग के निदेशक श्री संतोष चौबे द्वारा सम्मान निधि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। विगत वर्ष विश्वरंग हिंदी ओलंपियाड का भव्य उद्घाटन समारोह पूर्वक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव द्वारा पोस्टर लोकार्पण एवं वेबसाइट के शुभारंभ के साथ किया गया।

इसी तारतम्य में विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 के पोस्टर का लोकार्पण स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के वनमाली सभागार में गणमान्य अतिथियों द्वारा समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विश्व रंग के निदेशक और रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलगुरु डॉ. विजय सिंह, श्री धीर सिंह पवैया जी, संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, श्री गजेंद्र कुमार जी, प्रमुख, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र,नागपुर, डॉ पंकज कुमार, डीन, आईसर भोपाल, अध्यक्ष आई एम एस, भोपाल, डॉ जी. डी. मिश्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहें।

उल्लेखनीय है कि इसके साथ ही विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का पोस्टर रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय परिसर सहित आईसेक्ट समूह के सौ से अधिक केंद्रों पर समारोह पूर्वक लोकार्पित किया गया। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में पोस्टर का लोकार्पण कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, प्रतिकुलपति, डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, कुलसचिव, डॉ. संगीता जौहरी, टैगोर अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक डॉ. जवाहर कर्नावट, एजीयू की निदेशक समन्वय डॉ. पुष्पा असिवाल, विश्व रंग सीईओ श्री विकास अवस्थी, सचिव संजय सिंह राठौर, डॉ. गायत्री राजपूत, डॉ. अरुण पाण्डेय, डॉ. अनिल तिवारी, श्री राजेश पंडा, श्री राजेश शुक्ला, श्री कुणाल सिंह, श्री कमलेश शर्मा, श्री रामदीन प्रजापति, श्री प्रशांत सोनी, श्री दिनेश लोहनी श्री शिशिर सराठे आदि उपस्थित रहें। इसके पूर्व विश्व रंग फाउंडेशन में श्री संतोष चौबे जी की अध्यक्षता में विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 के आयोजन संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस वर्ष दस लाख विद्यार्थियों की विश्व रंग ओलंपियाड में भागीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

पोस्टर लोकार्पण के अवसर पर श्री संतोष चौबे ने विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व रंग हिंदी ओलंपियाड 70 से अधिक देशों में हिंदी के लिए काम करने वाले, हिंदी बोलने, सुनने, लिखने वाले लोगों को एक साथ लाने का कार्य करेगा। इसका भव्य आयोजन 14 सितम्बर से 30 सितम्बर तक भारत सहित वैश्विक स्तर पर किया जाएगा। इसमें भारत में कक्षा 1 से लेकर स्नातकोत्तर तक तथा विदेशों में लेवल 1 से लेवल 6 तक के विद्यार्थियों को छह स्तरों पर अवसर दिया जाएगा। हिंदी ओलंपियाड अपने स्वरूप और विस्तार के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक-शैक्षणिक अभियान बनकर उभरा है। विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 में विजेताओं को एक करोड़ के आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे, साथ ही ओलंपियाड में भागीदारी करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को आकर्षक प्रमाणपत्र भी प्रदान किये जायेंगे।

विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2026 के आयोजन में स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय, भोपाल (मध्यप्रदेश), डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), खंडवा (मध्यप्रदेश), वैशाली (बिहार), आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड), टैगोर।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के संपर्क अभियान 2026 को मिली बड़ी सफलता

• 1422 शिविरों में 46 हजार 398 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर निराकरण

भोपाल/ग्वालियर। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उनके घर के नजदीक ही निराकरण करने के उद्देश्य से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित संपर्क अभियान 2026 को सफलता मिली है। 14 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत भोपाल और ग्वालियर रीजन के 16 जिलों में व्यापक स्तर पर 1422 विशेष शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 46 हजार 398 उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

भोपाल रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- भोपाल रीजन के अंतर्गत सबसे अधिक 112 शिविर शहर वृत्त भोपाल में आयोजित किए गए जिसमें 2,833उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया, इसके साथ ही बैतुल वृत्त में 131 शिविरों में 4,984 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, सीहोर वृत्त में 95 शिविरों में 1,237 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, राजगढ़ वृत्त में 103 शिविरों में 616 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, नर्मदापुरम वृत्त में 99 शिविरों में 5,887उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, रायसेन वृत्त में 76 शिविरों में 3,020 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भोपाल (ग्रामीण) वृत्त में 75 शिविरों में 1,818 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, विदिशा वृत्त में 24 शिविरों में 2,464 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं हरदा वृत्त में 40 शिविरों में 7,471उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया है।

ग्वालियर रीजन के वृत्तों में लगे शिविर- ग्वालियर रीजन के अंतर्गत मुरैना वृत्त में 118 शिविरों में 1,467 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शहर वृत्त ग्वालियर में 88 शिविरों में 2,036 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, भिंड वृत्त में 85 शिविरों में 1,244 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, गुना वृत्त में 76 शिविरों में 2,368 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, ग्वालियर (ग्रामीण) वृत्त में 75 शिविरों में 899 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, श्योपुर वृत्त में 56 शिविरों में 1,260 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, दतिया वृत्त में 52 शिविरों में 2,721 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण, शिवपुरी वृत्त में 73 शिविरों में 2,120 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण एवं अशोकनगर वृत्त में 44 शिविरों में 1,953 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण किया गया।

इन शिकायतों और सेवाओं पर हुआ त्वरित काम

इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट समाधान करना है। शिविरों में मुख्य रूप से उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल, मीटर रीडिंग और अन्य बिलिंग संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया। साथ ही मात्र 5 रुपये में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पम्?प कनेक्शन प्रदान किये गए। वहीं भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्?थाई कनेक?शन विच?छेदन, अस्थायी कनेक्शन, ई-केवायसी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (हह्ष्ट), बंद/खराब मीटर बदलना, स्?मार्ट मीटर संबंधी शिकायतें, सर्विस केबल सुधार, वोल्टेज की समस्या और ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों, बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि भुगतान तथा अन्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किया गया।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 12 एवं 13 जून को मनाया जाएगा स्थापना दिवस

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कंपनी के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर 12 एवं 13 जून को कंपनी मुख्यालय के साथ ही भोपाल क्षेत्र तथा ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत वृत्त स्तर पर विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान गोविन्दपुरा स्थित मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में बिजली कार्मिकों द्वारा पौधरोपण करने के साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कंपनी के मैदानी कार्यालयों द्वारा भी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के साथ ही सहभागिता करने वाले कार्मिकों और ऐसे स्थानीय नागरिक जिन्होंने कंपनी कार्यों में सहयोग प्रदान किया है उन्हें भी प्रशस्?तिपत्र देकर सम्?मानित किया जाएगा। वहीं शत-प्रतिशत बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक?ताओं को सम्मानित किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन/प्रशासन) डॉ राकेश शर्मा ने बताया है कि राजधानी भोपाल में 12 जून को गोविन्दपुरा स्थित कंपनी मुख्यालय में स्थापना दिवस के अवसर पर प्रबंध संचालक द्वारा कार्मिकों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई जाएगी। इसी प्रकार कंपनी के कार्यक्षेत्र के सभी क्षेत्रीय, वृत्त, संभाग तथा विद्युत वितरण केन्द्रों पर कार्यालय प्रमुख के द्वारा कार्मिकों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की शपथ दिलाई जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

नितिन नवीन की 'पुरानी गद्दी' पर जेडीयू की नजर

• दीघा के बदले बांकीपुर की ख्वाहिश,अभी खाली है सीट

पटना (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई बांकीपुर में अभी तक बीजेपी उम्मीदवार की चर्चा चल रही थी। लेकिन अब ये सवाल सामने आया है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा या जदयू का। यह सवाल इसलिए कि जदयू के सूत्र बताते हैं कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जदयू के रणनीतिकारों ने दावा ठोक डाला है। बांकीपुर के विधायक रहे नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद अब बांकीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। इस बीच जदयू के रणनीतिकारों को यह ख्याल आया कि राजधानी पटना के मेन हार्ट लैंड में फुलवारी विधानसभा के अलावा कोई सीट नहीं है। इसलिए जदयू ने यह मोर्चा खाला है। इसके साथ साथ जदयू पटना के मेन हार्ट लैंड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। जदयू के रणनीतिकार इस मंशा को खारिज भी करना चाहते हैं कि पटना शहरी क्षेत्र से सिर्फ भाजपा ही जीत सकती है। दीघा विधानसभा जब अस्तित्व में आया तभी से जदयू ने अपना दावा उस पर ठोक रखा था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद जब साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो जदयू ने दावा ठोक दिया था।

• साल 2015 से बदला समीकरण- साल 2015 विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। तब एनडीए ने यह चुनाव महागठबंधन के साथ लड़ा था। तब बीजेपी की तरफ से संजीव चौरसिया और जनता दल यू से राजीव रंजन चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में जदयू हार गई थी।

'आईएम मुस्लिम',सामने आया आयुष उर्फ रहमान

• शामली धर्मांतरण केस में कहा-चांदनी को जेल भेजकर गलत किया

शामली (एजेंसी)। चांदनी कुरैशी के प्रेम में पड़कर निकाह करने वाले आयुष मलिक का खुलकर कहना है कि वह मुसलमान हैं। मीडिया से बातचीत में आयुष मलिक से मोहम्मद अली उर्फ रहमान बनने वाले शख्स ने अपनी बीवी और ससुर को जेल भेजने का विरोध किया। आयुष मलिक ने कहा–मैं मुस्लिम धर्म से बहुत सालों से प्रभावित था। इससे जुड़ी किताबों पढ़ा करता था। इस बीच, शामली के फिजियोथेरेपी सेंटर पर मेरी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई। हमारे बीच में दोस्ती हो गई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। मैंने उसे निकाह करने के लिए कहा पर वह तैयार नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से वह तैयार हुई तो उसे जेल भेज दिया गया। आयुष मलिक ने कहा–बहुत सारे लोगों ने प्यार के लिए अपना धर्म बदला है तो मैंने भी बदल लिया। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया।

• मैं और चांदनी साथ नहीं रहते थे- आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का कहना है कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा। पांच समय की नमाज पढ़नी पड़ेगी। मैंने और चांदनी ने शादी भले कर ली हो पर साथ में नहीं रहते। साथ रहने की बात की तो घरवाले नाराज हो गए।

फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतें गिरीं

• 32 की मौत,4.5 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठीं, 2 घंटे में 138 झटके आए

मनीला (एजेंसी)। फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक अब तक 32 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5.07 बजे आया। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में था। यह सारंगानी प्रांत के मासीम कस्बे से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में और 33 किलोमीटर की गहराई पर आया। अधिकारियों का कहना है कि यह इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप के बाद सुनामी भी आई।

• सैंटोर शहर में सबसे ज्यादा नुकसान– 7 लाख से ज्यादा आबादी वाले बंदरगाह शहर जनरल सैंटोस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यहां कई इमारतों में दरारें आ गईं, कुछ छोटी इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं और एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक शहर में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई और करीब 130 लोग घायल हुए हैं। दक्षिण कोटाबाटो, दावाओ ऑक्सीडेंटल और बालुत द्वीप समेत अन्य दक्षिणी इलाकों में भी 9 लोगों की मौत हुई। इनमें कुछ लोग गिरते मलबे, एक क्षतिग्रस्त मस्जिद और भूस्खलन की चपेट में आ गए। अधिकारियों ने बताया कि जनरल सैंटोस में एक दो मंजिला स्कूल इमारत के गिरने की खबर के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। आशंका जताई गई कि कुछ छात्र मलबे में फंस सकते हैं।

नीट में देश के युवाओं के साथ हुआ धोखा

• खड़गे ने कहा-गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें • कहा- एसआईआर में करोड़ों वोटर के नाम काटे • बोले-इंडिया ब्लॉक सीजेआई को लेटर लिखेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद हुई 7वीं बैठक में सोमवार को 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में हुई इस बैठक में उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल समेत कई शामिल हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इस गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, वह तुरंत इस्तीफा दें।

एनडीए सरकार पर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सबने मजबूती से एकजुट होकर डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है, ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने कई राजनीतिक और आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं।

• प्रयागराज जंक्शन और अलीगढ़ स्टेशन में होगी शुरुआत

रेलवे स्टेशनों पर खुलेंगे गेमिंग जोन और फन पार्क

प्रयागराज (एजेंसी)। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के साथ ही उनके मनोरंजन और सुविधा के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज मंडल ने एक बेहद महत्वाकांक्षी और अनूठी योजना तैयार की है। अब प्रयागराज मंडल के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर, विशेष रूप से जहां पुनर्विकास के तहत नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, वहां आधुनिक गेमिंग जोन सह फन पार्क खोले जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य स्टेशनों को केवल आवागमन का जरिया न बनाकर उन्हें एक आधुनिक हैंगआउट जोन के रूप में तब्दील करना है। इस वृहद योजना की शुरुआत प्रयागराज जंक्शन के अलावा अलीगढ़ स्टेशन से की जा रही है। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइंस स्थित सर्कुलेटिंग एरिया (सर्कुलेटिंग एरिया) में लगभग

20,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में एक अत्याधुनिक कमर्शियल हब विकसित करने जा रहा है। इस कमर्शियल हब को मुख्य रूप से चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं तक, यानी हर उम्र के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

• युवाओं के लिए अत्याधुनिक गेमिंग जोन – युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक अत्याधुनिक गेमिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। इसमें वर्चुअल रियलिटी (वीआर) गेम्स, हाई–स्पीड रेसिंग सिमुलेटर और नवीनतम वीडियो गेम्स की एक विस्तृत रेंज होगी। इसके अतिरिक्त, खेल प्रेमियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए यहां टर्फ स्पोर्ट्स की विशेष सुविधा दी जाएगी। यात्री और स्थानीय खेल प्रेमी यहां छोटी टर्फ पिच पर बॉक्स क्रिकेट और कोर्ट पर बैडमिंटन जैसे खेलों का आनंद ले सकेंगे।

विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हादसा, 8 मजदूरों की मौत

• 1600 सेंटीग्रेट पर पिघला गर्म लोहा क्रेन से ले जा रहे थे, बैलेंस बिगड़ने से उन पर ही गिरा

विशाखापट्टनम (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में करीब 1600 सेंटीग्रेट तापमान वाला पिघला हुआ लोहा (मोल्टन आयरन) मजदूरों पर गिर गया। हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, प्लांट में क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बकेट का संतुलन बिगड़ गया और उसमें भरा गर्म लोहा नीचे काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया।

जिस बंजर पहाड़ी पर घास नहीं उगती थी

वहां इंदौर के 75 साल के बुजुर्ग ने उगा दिए कश्मीर के केसर और स्पेन के जैतून

इंदौर (नप्र)। 75 वर्षीय पूर्व कॉलेज प्रिंसिपल एस.एल. गर्ग ने साल 2015 में महू के जामली गांव में एक ऐसी बंजर और पथरीली पहाड़ी देखी, जहां दूर-दूर तक न तो पानी का कोई स्रोत था और ना ही कोई छांव। स्थानीय किसानों के कहने पर गर्ग ने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई और अमेरिका में रह रहे बेटे की मदद से इस जमीन को 70 लाख रुपये में खरीद लिया। 2016 से उन्होंने यहां पौधे लगाना शुरू किया। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, लेकिन गर्ग के दिमाग में इस बंजर चट्टान को एक लिविंग लेबोरेटरी बनाने का जुनून सवार हो चुका था।

हर महीने 50,000 का खरीदा पानी- पहाड़ी पर पानी की एक बूंद नहीं थी। गर्ग ने सालों तक ग्रामीणों से टैंकरों के जरिए पानी खरीदा और हर महीने अपनी जेब से 50 हजार रुपये सिर्फ पानी पर फूंके।

आग की तबाही भी नहीं तोड़ पाई हौसला- साल 2019 में पहाड़ी पर भीषण आग लग गई, जिसने गर्ग के लगाए करीब 1,000 हरे-भरे पेड़ों को पल भर में राख कर दिया। लेकिन गर्ग ने हार नहीं मानी और दोगुने उत्साह से दोबारा पौधारोपण शुरू किया।

ग्लोबल पौधों का अनोखा बसेरा- इस 22 एकड़ के केसर पर्वत पर स्पेन के जैतून, थाईलैंड के ड्रैगन फ्रूट, मैक्सिको के खजूर और भारत की तमाम औषधीय प्रजातियों सहित 600 से ज्यादा किस्म के पौधे फल-फूल रहे हैं। लगातार पेड़ लगाने और ड्रिप इरिगेशन के लिए एक मानव निर्मित झील बनाने का असर यह हुआ कि सूखी पहाड़ी की मिट्टी में नमी लौट आई और इलाके का भूजल स्तर वापस ऊपर आ गया।

2019 में लग गई थी आग- इस सफर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2019 का वो अग्निकांड था, जिसने गर्ग की बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। कोई भी आम इंसान होता तो शायद वहीं रुक जाता, लेकिन गर्ग ने उस राख के ढेर से नए सिरे से शुरुआत की। उन्होंने पानी को सहेजने के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग और तालाब का ऐसा नेटवर्क तैयार किया कि आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। जो पहाड़ी कभी तपती धूप में आग उगलती थी, आज वो 50 हजार पेड़ों की घनी छांव के साथ पक्षियों, तितलियों और जंगली जानवरों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुकी है।

मिट्टी बदलकर उगा दिया कश्मीरी केसर

महू की काली कपास वाली मिट्टी को हटाकर वहां लाल मिट्टी बिछाई गई। कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मदद से 1,000 कॉर्म्स रोपे गए और आज वहां केसर की खेती कामयाब हो चुकी है।

अहिल्या नगरी इंदौर में ब्रिक्स कृषि महाकुंभ आज से

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, कृषि मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल, खेती-किसानी पर 5 दिन तक होगा मंथन

भोपाल/इंदौर (नप्र)। मध्य प्रदेश में 9 से 13 जून तक वैश्विक कृषि कूटनीति का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है, जहां ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अध्यक्षता में हो रहा यह आयोजन खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, छोटे किसानों के सशक्तिकरण और कृषि नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर ठोस दिशा तय करेगा। आज भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस आयोजन को भारत और विशेष रूप से इंदौर सहित मध्य प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताते हुए इसकी रूपरेखा साझा की।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश विश्व के विकासशील देशों की एक प्रभावशाली आवाज हैं। इन देशों के पास दुनिया की लगभग 42 प्रतिशत कृषि भूमि है और वैश्विक कृषि उत्पादन में भी इनकी हिस्सेदारी 42 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने बताया कि विश्व के करीब 58 करोड़ किसानों में से लगभग 70 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान ब्रिक्स देशों में रहते हैं। ऐसे में इन देशों के बीच होने वाला कृषि संवाद न केवल सदस्य देशों बल्कि पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की सोच कृषि को केवल उत्पादन तक सीमित रखने की नहीं है, बल्कि इसका दायरा खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन और सतत विकास तक विस्तारित है।

भारत की अध्यक्षता के दौरान 2016 में स्थापित ब्रिक्स एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह मंच आज अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की अध्यक्षता में अब तक कृषि कार्य समूह की आठ बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें खाद्य सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे विषयों पर व्यापक विचार-

विमर्श हुआ है। इंदौर में होने वाली बैठकों में इन विषयों को और आगे बढ़ाते हुए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य फोकस लघु और सीमांत किसानों पर रहेगा। श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसानों के सामने जोत का छोटा आकार, सीमित संसाधन और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ लागत घटाने, अनुसंधान के लाभों को किसानों तक पहुंचाने, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार कनेक्टिविटी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में महिलाओं और युवाओं की भूमिका को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्यबल में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जबकि युवा नई तकनीकों और नवाचार को तेजी से अपनाने में सक्षम हैं। 12 जून को महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा विषय पर विशेष चर्चा आयोजित की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की चार प्रमुख प्राथमिकताओं में खाद्य सुरक्षा और पोषण, कृषि व्यापार एवं सहयोग, जलवायु अनुकूल और सतत कृषि तथा नवाचार और अनुसंधान साझेदारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और बाजार पहुंच को बढ़ाना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन को कृषि के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और अत्यधिक वर्षा जैसी स्थितियां किसानों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में रीजेनेरेटिव फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि मिट्टी और पर्यावरण की गुणवत्ता भविष्य के लिए सुरक्षित रह सके।

खाद्य अपव्यय को भी एक बड़ी वैश्विक समस्या बताते हुए केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर वर्ष लगभग एक अरब टन खाद्यान्न बर्बाद होता है, जो न केवल संसाधनों की हानि है बल्कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भी एक प्रमुख कारण है। इस दिशा में भंडारण, परिवहन और सप्लाई चेन में सुधार के उपायों पर चर्चा होगी।

उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए केवल पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देकर आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और अन्य सुविधाओं के विकास को गति दी जा रही है, जिसका दायरा अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

भारत में प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में डिजिटल और तकनीकी क्रांति का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में अब तक 9.80 करोड़ किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं। इससे किसानों की जानकारी एकीकृत रूप में उपलब्ध हो रही है और योजनाओं, ऋण तथा अन्य सेवाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को सलाह, संसाधन प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है।

शिवराज सिंह ने बताया कि बैठक के कार्यक्रम के तहत 9 से 11 जून तक कृषि कार्य समूह की अधिकारी स्तर की बैठकें होंगी, जबकि 12 और 13 जून को कृषि मंत्रियों की बैठक आयोजित होगी। इस दौरान एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें भविष्य के सहयोग और साझा रणनीति का खाका प्रस्तुत किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन को सांस्कृतिक रूप से भी विशेष स्वरूप दिया गया है। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को इंदौर और मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, खानपान और परंपराओं से परिचित कराया जाएगा। राजवाड़ा, 56 दुकान और मांडू जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कार्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा 'ब्रिक्स वाटिका' के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा।

शिवराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन न केवल कृषि क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई दिशा देगा, बल्कि भारत की नेतृत्व क्षमता और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत करेगा।

संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन का शिखर प्रदर्शन

यूनिट-3 ने लगातार 100 दिन बिजली उत्पादन कर रचा इतिहास

भोपाल (नप्र)। प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के संजय गांधी थर्मल पॉवर स्टेशन बिरसिंगपुर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्टेशन की यूनिट नंबर 3 ने बीते 27 फरवरी से बिना रुके लगातार 100 दिनों तक बिजली पैदा करने का स्वर्णिम आंकड़ा छू लिया है। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भी कंपनी की कुल 13 उत्पादन इकाइयों ने 100 से अधिक दिनों तक लगातार निर्बाध बिजली उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया था। इस शानदार ट्रैक रिकॉर्ड में अकेले संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंगपुर का दबदबा रहा; जहां इसी यूनिट-3 ने पहले भी एक बार यह मुकाम हासिल किया था, वहीं स्टेशन की यूनिट-4 दो बार और यूनिट-5 ने एक बार इस ऐतिहासिक उपलब्धि को अपने नाम दर्ज कराया था।

सटीक परिचालन से गढ़े गए दक्षता के नए मानदंड

इस रिकॉर्ड परिचालन अवधि के दौरान यूनिट ने 89.18 प्रतिशत का प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर बनाए रखा, जो बिजली उत्पादन के लिए इस इकाई की उच्च उपलब्धता और तकनीकी मजबूती को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही, इकाई ने 80.07 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर दर्ज कर अपनी वास्तविक उत्पादन क्षमता के कुशल उपयोग का लोहा मनवाया। ऊर्जा दक्षता के मोर्चे पर भी प्रबंधन का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जहां आंतरिक सहायक विद्युत खपत को महज 9.17 प्रतिशत पर सीमित रखकर बिजली की बड़ी बचत की गई।

उत्पादन इकाइयाँ उच्चतम विश्वसनीयता के साथ काम करने में सक्षम

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने इस गौरवमयी उपलब्धि पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने कहा, हमारे इंजीनियरों और तकनीकी टीम ने उत्कृष्ट संधारण और कुशल संचालन के दम पर बार-बार यह साबित किया है कि कंपनी की बिजली उत्पादन इकाइयाँ उच्चतम विश्वसनीयता के साथ काम करने में पूरी तरह सक्षम हैं। यही वजह है कि हमारी इकाइयाँ लगातार राष्ट्रीय स्तर के कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन का एक बेहद मजबूत रिकॉर्ड बना रही हैं। उन्होंने कहा यह उपलब्धि तकनीकी कार्मिकों एवं ठेका श्रमिकों की सतत निगरानी, समर्पण तथा समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण संधारण का परिणाम है।

डायरेक्टर टेक्निकल सुबोध निगम ने कहा कि यह सफलता पूरी टीम के आपसी तालमेल, सक्रिय कार्यप्रणाली और संकट के समय त्वरित फैसलों का नतीजा है। उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे सभी विद्युत गृह भविष्य में भी प्रदेश को निर्बाध और भरोसेमंद बिजली देने में हमेशा आगे रहेंगे।

सैफ अली खान की भोपाल संपत्तियों पर संकट...

नवाब परिवार के खंगाले जाएंगे रिकॉर्ड, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

भोपाल (नप्र)। भोपाल में अरबों रुपये मूल्य की नवाबी संपत्तियों और शत्रु संपत्ति को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नवाब परिवार से जुड़ी जमीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड की दोबारा जांच कराने की मांग उठी है। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें भारत सरकार और तत्कालीन भोपाल रियासत के बीच वर्ष 1949 में हुए मर्जर एग्रीमेंट को जांच का आधार बनाने की मांग की गई है। मामले में अभिनेता सैफ अली खान, शर्मिला टैगोर, सोहा अली खान और सबा अली खान समेत नवाब परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी चर्चा में हैं।

शत्रु संपत्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए जांच समिति का गठन

भोपाल में शत्रु संपत्तियों की पहचान और सत्यापन को लेकर कस्टोडियन विभाग के निर्देश पर पहले से जांच प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कलेक्टर द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। इसी बीच समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री ने मामले में नए तथ्य और सवाल उठाते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट सुमित कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपकर मांग की है।

1370 एकड़ भूमि और पांच प्रमुख लोकेशन पर कानूनी पेच

कोहेफिजा, नयापुरा, हलालपुर सहित शहर के कई क्षेत्रों में स्थित नवाबी संपत्तियों को लेकर कानूनी विवाद बना हुआ है। ज्ञापन में बताया गया है कि सैफ अली खान ने पूर्व में उच्च न्यायालय में दायर एक मामले में भोपाल की लगभग 1370 एकड़ भूमि को नवाब परिवार की संभावित निजी संपत्ति बताया था। अब जांच समिति से इन जमीनों की वर्तमान स्थिति और कानूनी दर्जे को स्पष्ट करने की मांग की गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विवादित संपत्तियों की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।

पाकिस्तान पलायन से जुड़ा है शत्रु संपत्ति का मामला

विवाद की जड़ नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी के पाकिस्तान चले जाने से जुड़ी हुई है। नियमों के अनुसार उनके नाम दर्ज संपत्तियां शत्रु संपत्ति की श्रेणी में आ सकती हैं। इसी कारण संबंधित जमीनों और जायदाद की पहचान एवं स्वामित्व को लेकर जांच की मांग लंबे समय से उठ रही है। इस संबंध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी शिकायतें और मांग पत्र भेजे जा चुके हैं।

मर्जर एग्रीमेंट को जांच का आधार बनाने की मांग

उन्होंने एडीएम को दिए ज्ञापन में कहा है कि भारत सरकार और नवाब हमीदुल्ला खान के बीच 29 अप्रैल 1949 को हुए मर्जर एग्रीमेंट की प्रति के आधार पर संपत्तियों की जांच कराई जानी चाहिए। एग्रीमेंट में सरकारी भूमि और नवाब परिवार की निजी संपत्तियों का अलग-अलग विवरण दर्ज है। मांग की गई है कि इसी सूची को आधार बनाकर यह तय किया जाए कि कौन-सी संपत्तियां सरकारी और कौन-सी निजी हैं।

वन रक्षक-जेल प्रहरी परीक्षा को लेकर एनएसयूआई ने घेरा दफ्तर

एमपी कर्मचारी चयन मंडल कार्यालय पहुंचकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन ; बोले- दोषियों पर हो कार्रवाई

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा-2026 की परीक्षा कैंसिल होने पर सोमवार को एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारी-कार्यकर्ताओं ने व्यापमं चौराहा स्थित कर्मचारी चयन मंडल के दफ्तर का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार एवं भोपाल जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इसके बाद संयुक्त परीक्षा नियंत्रक दिनेश अग्रवाल को अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षार्थियों को राहत प्रदान करने की मांग की गई। उपाध्यक्ष परमार ने बताया, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 7 जून को आयोजित वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा-2026 के दौरान प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को गंभीर

अव्यवस्थाओं, तकनीकी खामियों एवं प्रशासनिक लापरवाही का सामना करना पड़ा।

सैकड़ों किमी तय की दूरी- प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुंचे थे। कई अभ्यर्थियों ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद यात्रा, आवास, भोजन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च कर परीक्षा में शामिल होने की तैयारी की थी, किंतु परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के बाद उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक बैठाकर रखा गया। बाद में तकनीकी खामियों का हवाला देकर परीक्षा निरस्त कर दी गई।

परमार ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी वर्षों की मेहनत, समय एवं संसाधन लगाकर परीक्षा देने पहुंचते हैं। ऐसे में परीक्षा के दिन इस प्रकार की अव्यवस्था न केवल उनकी मेहनत को प्रभावित करती है, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति एवं भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

परीक्षा में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप

जिलाध्यक्ष तोमर ने बताया, परीक्षा के दौरान सामने आई घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि परीक्षा आयोजन में गंभीर स्तर की लापरवाही बरती गई है। यदि तकनीकी व्यवस्थाएं समय रहते तय की जाती तो हजारों अभ्यर्थियों को इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तोमर ने आगे कहा कि साथ ही इस पूरे घटनाक्रम ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों के बीच यह आशंका व्याप्त है कि कहीं न कहीं परीक्षा संचालन में गंभीर अनियमितताएं एवं धांधलियां हुई हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।जिला उपाध्यक्ष अमित हाटिया ने कहा, कर्मचारी चयन मंडल की यह जिम्मेदारी है कि भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुचारू व्यवस्थाओं के साथ संपन्न हों तथा अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

गर्भावस्था में समय पर जांच एवं उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से सुरक्षित मातृत्व होता है सुनिश्चित : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सुरक्षित मातृत्व प्रत्येक महिला का अधिकार है। राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश की सभी गर्भवती महिलाओं एवं उनके परिजनों से अपील की है कि वे 9 जून को आयोजित विशेष प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में पहुंचकर निःशुल्क जांच, परामर्श एवं उपचार सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था दी समय पर जांच एवं उच्च जोखिम स्थितियों की शीघ्र पहचान से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा है कि इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में संचालित करते हुए प्रत्येक गर्भवती महिला तक गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में और कमी लाई जा सके।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत मध्यप्रदेश में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अभियान के तहत पंजीकृत 14.31 लाख गर्भवती महिलाओं में से 10.25 लाख महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) की गई, जो कुल पंजीकृत गर्भवतियों का लगभग 72 प्रतिशत है। जांच के दौरान 2.94 लाख महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेगनेंसी-एचआरपी) के रूप में चिन्हित किया गया, जिनमें से 2.60 लाख अर्थात 88 प्रतिशत महिलाओं को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक उपचार, प्रबंधन एवं रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सुश्री दिशा प्रणय नागवंशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफलतापूर्वक 10 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 9 जून को प्रदेश के सभी जिलों में विशेष पीएमएसएमए शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। विशेष शिविरों में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच, नवीन एवं छूटी हुई गर्भवतियों का पंजीयन, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान, उपचार एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा। महिलाओं की रक्तचाप, वजन, बीएमआई, मेडिकल एवं प्रसूति इतिहास की जांच के साथ ही आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण भी किए जाएंगे।

मप्र 7.63 लाख से अधिक बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण कर देश के शीर्ष राज्यों में शामिल: उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि जनभागीदारी, स्वास्थ्य अमले की प्रतिबद्धता और प्रभावी नेतृत्व के बल पर बड़े से बड़े जनस्वास्थ्य अभियानों को समय से पहले सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम, शिक्षकों, जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें सफलता के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रदेश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाकर सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 को देशव्यापी एचपीवी(ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया था। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान में मध्यप्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य अमले, सहयोगी विभागों की प्रतिबद्धता एवं सतत मॉनिटरिंग के परिणामस्वरूप प्रदेश में 7.63 लाख से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। यह अभियान मूल रूप से 90 दिनों के लिए निर्धारित था, लेकिन मध्यप्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य को मात्र 60 दिनों में ही पूर्ण कर लिया जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता और प्रभावी क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण है। सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है तथा इसके अधिकांश मामलों का प्रमुख कारण एचपीवी संक्रमण होता है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह ऐसा कैंसर है जिसे प्रभावी टीकाकरण के माध्यम से काफी हद तक रोका जा सकता है। एचपीवी वैक्सीन बालिकाओं को भविष्य में इस गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने का सुरक्षित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक उपाय है। अभियान की सफलता में स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता रही।

संपादकीय

बीजेपी ने फंसाया पेंच!

जैसी कि उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में विपक्षी कांग्रेस को राज्यसभा की इकलौती सीट आसानी से नहीं जीतने देगी, वैसा ही हो भी रहा है। भाजपा ने आरंभिक असमंजस के बाद अब तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार महेश केवट के रूप में उतार दिया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की जीत की राह मुश्किल हो गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कांग्रेसी अपनी सीट आसानी से जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर की हकीकत बहुत आश्वस्त करने वाली नहीं है। गौरतलब है कि मप्र से राज्यसभा की तीन सीटें सम्बन्धित सदस्यों के रिटायरमेंट के कारण खाली हो रही हैं। इनमें से एक सीट दिग्विजयसिंह की भी है, जो खुद ही तीसरी बार रास जाने से इंकार कर चुके हैं। बाकी दो सीटें बीजेपी की हैं। राज्यसभा के चुनाव में विधायक वरीयता के हिसाब से मतदान करते हैं। मप्र में अभी तक माना जा रहा था कि चूंकि यहां बीजेपी की दो और कांग्रेस की एक सीट आसानी से निकल जाएगी, ऐसे में मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राज्यसभा टिकट के लिए कांग्रेस में मची भीतरी खींचतान के बाद भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी भी उतारने का फैसला नामांकन भरने की अंतिम तिथि के कुछ घंटों पहले किया। बताया जाता है कि मीनाक्षी को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस में बहुत से लोग खुश नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद राज्यसभा जाना चाहते थे तो पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी इस पद के लिए उछला। इनके अलावा भी कई नाम चर्चा में थे। लेकिन मीनाक्षी नटराजन ने बाजी मारी। मीनाक्षी राहुल गांधी की पसंद बताए जाते हैं। वो मप्र की हैं और उनकी गणना कांग्रेस के पढ़े-लिखे नेताओं में की जाती है। वो 2009 में मंदसौर से कांग्रेस सांसद का चुनाव भी जीत चुकी हैं। मीनाक्षी की उम्मीदवारी को सार्वजनिक तौर पर सभी ने समर्थन किया है। दिग्विजयसिंह ने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपना समर्थन जताया तो दूसरी तरफ उनके ही खास समर्थक समझे जाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी की उम्मीदवारी पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। पार्टी में अंदरखाने और भी नाराज बताए जाते हैं। भाजपा ने शुरू में कहा कि तीसरा प्रत्याशी उतारने का उसका कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसे ही राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में खींचतान की खबर मिली भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी को तीसरा प्रत्याशी उतारना चाहिए। इसके बाद घटनाचक्र तेजी से घूमा और रविवार रात महेश केवट का नाम जाहिर कर दिया गया। भाजपा प्रत्याशी महेश केवट वर्तमान में मप्र मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं।

मप्र विधानसभा में पार्टीवार विधायकों का जो गणित है, उसके हिसाब से एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों का समर्थन चाहिए। भाजपा के पास कुल 164 विधायक हैं। इस हिसाब से वो दो सीटें आसानी से जीत लेगी। यानी पार्टी के दो प्रत्याशियों तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल की जीत तय है। उसके बाद भी भाजपा के पास 48 विधायक बाकी रहेंगे। यानी तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोट चाहिए। सदन में 1 विधायक निर्दलीय है। जबकि विजयपुर विधायक और को वोट देने का अधिकार नहीं है और दतिया के कांग्रेस विधायक का चुनाव रद्द हो चुका है। बीना की कांग्रेस विधायक भी संभवतः भाजपा को वोट करेंगी। अगर 10 विधायक क्रॉस वोट कर दें तो भाजपा का तीसरा प्रत्याशी भी जीत सकता है। हालांकि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट करने पर विचार कर रही है ताकि कोई गड़बड़ न हो। जबकि भाजपा आश्वस्त है कि कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग होगी।

कॉकरोच का समर्थन विपक्ष का विरोध नहीं

नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

कुछ लोग विपक्ष को व्यक्ति वाचक संज्ञा मानते हैं। कुछ लोग दलवाचक संज्ञा मानते हैं तो कुछ लोग गठबंधन वाचक। वे लोग महीने भर पहले गैस के रूप में उदित हुई कॉकरोच जनता पार्टी के द्रव में परिवर्तित होने से भयभीत हैं कि कहीं उनका संज्ञापद छिन न जाए। इस भयातुर समूहों में वह कांग्रेस पार्टी भी भयभीत है जो 140 साल पुराना है और जिसका अगर पचास पचपन साल के शासन का इतिहास रहा है तो कम से कम सत्तर साल आंदोलन का इतिहास रहा है। वे इस बात से एकदम खुश नहीं हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी नामक नवोदित प्रहसन केंद्रित संगठन से सत्तापक्ष भी आशंकित है। इसकी वजह यह है कि विपक्ष ने हार को अपनी नियति मान लिया है। विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के तमाम समर्थक बौद्धिक कॉकरोच जनता पार्टी पर सत्तापक्ष से अधिक घातक हिट लेकर टूट पड़े हैं। बिना इस बात का ज्ञान रखे कि उनके हिट का आजकल किसी पर कोई असर नहीं होता वे समझते हैं कि वे इस हिट से 1975 के जेपी आंदोलन और 1967 के लोहिया आंदोलन का भी नामोनिशान मिटा डालेंगे। ऐसे लोगों से कुछ प्रतिवेदन किया जाना अपना फर्ज बनता है, मानना न मानना उनके अपने डर और बौद्धिक अहंकार पर निर्भर करता है।

अगर हम विपक्ष को संज्ञा के बजाय एक क्रिया मानें और उसे विरोध शब्द से संबोधित करें तो शायद कॉकरोच जनता पार्टी या देश के युवाओं में इस व्यवस्था और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर पैदा हुए विरोध को समझ कर उस पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकेंगे? लोकतंत्र में विरोध या विपक्ष एक मानक और सम्मानित क्रिया है। उसके बिना लोकतंत्र के पहिए रुक जाते हैं उसमें जंग लग जाता है उस तालाब का पानी सड़ने लगता है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के कमल खिलने की उम्मीद रहती है। (यहां कमल का मतलब किसी दल विशेष के चुनाव चिह्न से नहीं है। जो अब प्लास्टिक का हो चुका है।) अच्छी बात है कि 6 जून को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर युवा ही नहीं बुजुर्ग भी आए और सीपीआई की एनी राजा, सीपीआईएमएल के दीपंकर भट्टाचार्य और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पदाधिकारी और तमाम वामपंथी लोग भी पहुंचे। उनके पहुंचने का असर यह हुआ कि चंद दिनों पहले गांधीवादी बने कुछ मार्क्सवादी बौद्धिक इस आंदोलन को सीधे-सीधे दक्षिणपंथी आंदोलन साबित नहीं कर पाए। हालांकि उनका पूरा प्रयास इसी का था। कॉकरोच जनता पार्टी को संज्ञा के बजाय क्रिया कहना इसलिए उचित है क्योंकि वह इस देश में सरकार के हिंदू मुस्लिम और सवर्ण अवर्ण के विभाजन में आकर भटक चुके युवाओं को व्यवस्था का असली चेहरा दिखाने की एक क्रिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक व्यंगात्मक टिप्पणी को अपनी नियति या नाम बना चुका युवाओं का यह समूह कोई क्रांति कर देगा या कोई पार्टी बनाकर चुनावों में पारंपरिक विपक्ष

का स्थान ले लेगा या सत्तारूढ़ दल का तख्तापलट कर देगा, भारत में ऐसी संभावना दूर दूर तक दिखती नहीं। धर्मनिरपेक्ष और कांग्रेस की सत्ता कायम करने में लगे बौद्धिकों की यह आशंका सही हो सकती है कि यह लोग भी भारत बनाम भ्रष्टाचार की तरह से आम आदमी पार्टी के रूप में प्रकट होंगे और देश में फासीवादी ताकतों को और मजबूत करेंगे, लेकिन अभी तक इस प्रयास और इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। वह अभी तक युवाओं का स्वतःस्फूर्त आंदोलन जैसा ही दिख रहा है और 2010-11 में यूपीए सरकार ने भारत बनाम भ्रष्टाचार के नेताओं की जितनी मिजाजपुर्सी की थी अभी की सरकार उससे बहुत कम कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर अभी भी इस गलतफहमी में है कि वह सत्ता में है और यह आंदोलन उसके विरुद्ध चल रहा है तो यह उसकी बुद्धि की बलिहारी है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा जगत और विशेषकर नीट, सीबीएसई में व्याप्त भयंकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन कर रही है और उसे इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उसके नेता राहुल गांधी मौजूदा सरकार और उसके नेतृत्व के सामने सीना तानकर खड़े हैं इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं है। इसीलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें देश का हर समझदार और लोकतांत्रिक व्यक्ति अपना नैतिक और भौतिक समर्थन देने को तैयार है।

लेकिन इस सरकार ने पारंपरिक विपक्ष के दमन और उसे नष्ट करने का जो अभियान छेड़ रखा है, वह एक हद तक इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुआ। आपातकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में विपक्ष के एकजुट होने और प्रतिरोध करने का लोकवृत्त काफी खुला हुआ था। आज अगर हम हाल में मृत्यु को प्राप्त हुए जर्मन दार्शनिक जुगरेन हैबरमास के शब्दों में भारत के विपक्षी लोकवृत्त की बात करें तो कहा जा सकता है कि बिना आपातकाल के ही वह आपातकालीन प्रतिबंधों का शिकार है। इसी स्थिति को देखते हुए हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी गौरतलब है। एक सदस्यीय बेंच के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा है कि अफसर सरकार और अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति अधिक वफादार हैं न कि संविधान के प्रति। गाजियाबाद के एक परिवार द्वारा लेन देन में कुछ धांधली हुई तो प्रशासन ने पूरे परिवार पर गैंगेस्टर कानून लगा दिया। जबकि संगठित रूप से अपराध करने का कोई प्रमाण अफसरों के पास नहीं था। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर कानून हटा दिया है।

इस सिलसिले में हमें अभिजीत दीपके के इस बयान को देखना चाहिए कि मेरी मां उस समय ज्यादा दुखी नहीं थीं जब मैं अमेरिका जा रहा था लेकिन जब मैं लौटने लगा तो वे ज्यादा दुखी और असुरक्षित महसूस कर रही थीं। उन्होंने जंतर मंतर पर दिए संबोधन में न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा बल्कि हिंदू मुस्लिम विभाजन का विरोध किया और युवाओं में बनी हुई दहशत को तोड़ने का प्रयास किया। बहुत संभव है कि हार्दिक पटेल की तरह ही अभिजीत दीपके की स्थिति हो और सरकारी दमन के बाद वे अपने प्रतिरोध कार्यक्रम को वापस भी ले लेकिन अगर इससे देश के युवाओं में सत्तर और अस्सी के दशक की प्रतिरोध की चेतना किसी हद तक वापस लौटती है तो उसे एक उपलब्धि मानना होगा। यह आशंका जितनी प्रबल है कि इस आंदोलन का लाभ सत्तापक्ष बखूबी उठा लेगा, उतनी ही यह संभावना भी है कि इससे विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाएगा। क्योंकि एक ओर यह आंदोलन उन्हीं बातों को रख रहा है जिन्हें विपक्षी नेता रखते रहे हैं। जैसे कि संविधान सम्मत शासन, शासन करने वालों की जवाबदेही और हिंदू मुस्लिम एजेंडे की समाप्ति और बेरोजगारी मिटाना, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, ग्रामीण शिक्षा में गुणवत्ता लाना और न्यायपालिका जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बहाल करना। साथ ही वे आंबेडकर के सपनों का लोकतंत्र कायम करने की बात कर रहे हैं जो कि इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह इस दौर की विडंबना है जो जो आंबेडकर आजाद भारत में आंदोलन न करने का सुझाव देते थे उन्हीं के अनुयायी गांधी के रास्ते पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। यह हमारे इतिहास के दो महापुरुषों के समन्वय का सर्वश्रेष्ठ अवसर भी है। भले ही युवा भारत के मुख्य न्यायाधीश का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं लेकिन अहंकार में दिए गए एक बयान के कारण उनका भारत से लंदन तक जो माखौल उड़ रहा है और विरोध हो रहा, उसे उन्हें समझना चाहिए। दूसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस सरकार में बैठे लोगों में भयंकर किस्म का अहंकार और अपने को सही बताने की प्रवृत्ति है। आप केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान देख लीजिए कि यूपीए की तरह इस मामले में कोई मंत्री शामिल नहीं है, यह तो गड़बड़ी स्वायत्त संस्थाओं ने की है। उधर भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि युवा सकारात्मक दिशा में राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं जबकि यह आंदोलन व्यवस्था विरोध का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे में तय है कि यह टकराव एक हद तक आगे बढ़ेगा।

जो लोग युवाओं के इस आक्रोश की विफलता की पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं वे इतिहास में नियतिवाद के शिकार हैं। वे हर चीज को यह मान कर चलते हैं कि सारी चीजें पहले से तय हैं। या तो उन्हें बड़ी ताकतें संचालित कर रही हैं या फिर कोई ऐसा नियम है जिससे सब चीजें संचालित हो रही हैं। वे मनुष्य की भूमिका को एकदम नकार कर चल रहे हैं। उन्हें इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा की पुस्तक 'अधूरी क्रांतियों का इतिहास बोध' देखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि क्रांतियों का अधूरा रह जाना इतिहास सिद्ध है, पर उनका अमर रहना भी उतना ही....। वे लिखते हैं, 'संक्रमण के इस दौर में इतिहास बोध और प्रयोगधर्मिता का विस्तार हो रहा है, कोई एक मंजिल, कोई एक राह, कोई एक क्रांति ही चरितार्थ होती न दिखे–कई मंजिलें, कई राहें, कई क्रांतियां अंगड़ाई लेती दिख रही हैं, विकल्प अनिश्चित लगे तो क्या हुआ? समवेत प्रयास न हो रहे हों तो क्या हुआ? हालात ही कुछ ऐसे हैं कि कोई चैन से बैठ नहीं सकता।'

तेजी से बदल रहा है बंगाल

राजनीति

अवधेश कुमार
लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के अल्पकाल में ही स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि केवल ममता सरकार की विचारधारा और दिशा के बिल्कुल उलट शुभेंदु सरकार ने यू टर्न ही नहीं किया बल्कि सारे कील कांटों को उखाड़ते, ध्वस्त करते तीव्र गति से शासन की गाड़ी वहां पहुंच रही है जहां से बंगाल शांत और स्थिर हो सामान्य राज्य के रूप में गतिविधियों का निर्धारण करे। शुभेंदु सरकार ने कुछ फैसले किए तथा कुछ प्रभाव में ही परिवर्तन आ गया। इनमें केवल केंद्रीय योजनाओं को लागू करना ही नहीं है। आप चाहे भाजपा के जितने आलोचक हों क्या किसी ने कल्पना की थी कि सरकार आने के हफ्ते भर के अंदर ही राज्य से टीएमसी द्वारा लगाए अवैध टोल बूथ हट जाएंगे,बैरिकेड समाप्त हो जाएंगे, हफ्ते वसूली का धंधा खत्म हो जाएगा, यह हो गया। ममता ने स्वयं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति चिंता प्रकट करते हुए रात में न निकलने का आग्रह किया था। सरकार बदलते ही बंगाल अपने स्वभाव,संस्कृति और चहल-पहल में वापस दिख रहा है। महिलाएं देर रात आती- जाती दिखाई दे सकती है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कोलकाता समेत कई जिलों में रात की पुलिस पेट्रोलिंग काफी बढ़ा दी गई है। आम प्रतिक्रिया देख लीजिए सोशल मीडिया से लेकर मुख्य मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि अब सरकार बदली है ऐसा महसूस हो रहा है। बकरीद के दिन वर्षों बाद सड़कों की बजाय मैदानों और मस्जिदों में नमाज पढ़े गये।

किसी सरकार की दिशा का संकेत होता है और अगर वैचारिक और प्रशासनिक दिशा स्पष्ट हो, उनके प्रति प्रतिबद्धता और व्यवहार में प्रखरता हो तो उसका इकबाल कायम होता है। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद ऐसा लग रहा था मानो बंगाल को संभालना कठिन होगा। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा मानो यह वो बंगाल है ही नहीं जिसे हम 4 मई के चुनाव परिणाम के पूर्व या उसके दो चार दिनों बाद तक देख रहे थे। कोलकाता से आसनसोल तक अवैध निर्माण के विरुद्ध बुलडोजर करवाई का आक्रामक हिंसक विरोध पूर्व सरकार की तस्वीर पेश कर रहा था। पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद क्या हुआ यह महत्वपूर्ण है। फुटेज से पत्थरबाजों और दंगाइयों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई हो रही है तथा पुलिस ने लाउडस्पीकर में ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने हिंसा और तोड़फोड़ की है उनकी संपत्ति से इसकी वसूली की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के विरुद्ध यही नियम अपनाया और उसके परिणाम काफी हद तक आए। बंगाल में इसकी कल्पना ही नहीं थी जो सामने है।

भाजपा ने चुनाव अभियान में कानून और व्यवस्था कायम करने, महिला सुरक्षा, अवैध घुसपैठ रोकने, घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमा सुरक्षा एवं अंतरिक्ष सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने, तुष्टिकरण की समाप्ति एवं हिंदुओं के साथ हुए अन्याय का परिमार्जन, भ्रष्टाचार का अंत,प्रदेश को विकास एवं सांस्कृतिक गरिमा की पटरी पर वापस लाने आदि वायदे किए थे। मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही शुभेन्दु ने बांग्लादेश की सीमा पर घेराबंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल को भूमि सौंपने का आदेश दिया जिसे 45 दिनों में पूरा हो जाना है। 450 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र हैं जहां घेरा लगाना बाकी है उसकी जमीन मिली नहीं। मिनट में यह काम हो गया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला नेशनल हाईवे 10 और नेशनल हाईवे 110 के सात हिस्से केंद्र सरकार को सौंपना है। इनमें से पांच चिकन नेक या सिलीगुड़ी गलियारा से गुजरते हैं। चिकन नेक का 120 किलोमीटर इलाका पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को भारत के साथ जमीन से जोड़ता है। यह बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तीन देशों से लगता है और चीन भी यहां से निकट है। चिकन नेक कट जाए तो पूर्वोत्तर से भारत का सीधा जमीनी संपर्क खत्म हो जाएगा। दिल्ली दंगों के आरोपी सरजिल इमाम को उच्चतम न्यायालय ने आज तक जमानत इसीलिए नहीं दी कि उसने मुसलमानों के द्वारा चिकन नेट काट कर भारत को खंडित करने की बात की थी। संयोग से उस पूरे क्षेत्र में भारत के अंदर बंगाल और बिहार दोनों और मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से अधिक है तथा दूसरी और बांग्लादेश है। मुस्लिम आबादी को भड़का कर चिकन नेक काट कर शेष पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने का विचार बांग्लादेश के पूर्व शासक मोहम्मद यूनुस से लेकर वहां जेन जी आंदोलन तथा जमात ए इस्लामी के नेताओं के सामने आए। ममता सरकार ने केंद्र के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और इस कारण वहां रक्षा और नागरिक दोनों प्रकार के आधारभूत संरचनाओं की कमी रही। अवैध घुसपैठ के साथ अनेक भारत विरोधी गतिविधियां,अवैध पशुओं एवं सामग्रियों की तस्करी आदि को पूरी तरह रोक पाना कठिन था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मिलकर इसका विकास करेगा। यानी आंतरिक और सीमा सुरक्षा और दूसरे रूप में कहें तो घुसपैठियों को रोकने के लिए सरकार ने पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई है।

कट मनी और भ्रष्टाचार तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की व्यापक छानबीन और कार्रवाई के लिए दो उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे ही आदेश अन्य मामलों में दिए जा रहे हैं जिन्हें पूर्व सरकार ने रोक कर रखा था। आप जानते हैं कि संदेशखाली से लेकर आईजी कर और यहां तक कि मुर्शिदाबाद के दंगों में महिलाओं के साथ व्यवहार बंगाल में प्रमुख मुद्दा रहा है। कट मानी और भ्रष्टाचार का अनुभव ऐसा था मानो यह सरकारी प्रक्रिया का ही अंग हो। आप देख लीजिए वही पुलिस प्रशासन और माहौल कितना बदला है।अवैध कब्जों से मुक्ति बंगाल की ऐसी चुनौती है जिससे निपटना यानी इतिहास की धारा बदल देना होगा। एक पार्टी के लोगों का ही पूरे प्रदेश में कब्जा है। तृणमूल ने सत्ता में आते ही कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के दफ्तरों व अन्य स्थान कब्जाये, इसके साथ नेताओं ने प्रशासन की मिली भगत से सरकारी व निजी जमीन, मकान सब पर भयानक रूप से कब्जे किए। माफिया तंत्र भूमि का उत्पन्न हुआ जिसने न जाने कितने लोगों को स्थान छोड़ने को विवश कर दिया। इसी तरह धर्म स्थलों पर कब्जे हुए या उन्हें जबरन बंद रखने को भी विवश किया गया। लगातार उन अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस और वामपंथी दलों तक के दफ्तर मुक्त कर भाजपा के लोगों ने कई जगह सौंप दिया। कुछ डर से ही छोड़ कर भाग गए। कई धर्मस्थल तो जनता ने हीं मुक्त करा लिए।

वास्तव में शुभेंदु सरकार ने भाजपा की विचारधारा को सत्ता नीति में अपनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है। सड़कों पर नमाज पढ़ने का अंत करने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया। राज्य के इमामों, मुअज्जिनों और पुजारियों को दिया जाने वाला सरकारी भत्ता (मानदेय) 1 जून से समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार का एक बड़ा फैसला अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 17 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना तथा इसे केवल 66 हिंदू जातियों तक ही सीमित रखना है। पिछड़ी जाति की सूची में से मुसलमान की जातियों को पूरी तरह हटा दिया। ममता बनर्जी ने 2024 में 71 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया था जिनमें 65 मुस्लिम समुदाय के थे। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा पिछड़ी जाति का आरक्षण देने के लिए ही श्रेणी ए बनाकर 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित किया था। इसके पहले पिछड़े वर्ग के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण था। साफ था कि केवल वोट बैंक की दृष्टि से मुसलमानों को पिछड़ी जाति में शामिल कर अतिरिक्त आरक्षण का अनुपात लाया गया। इस तरह शुभेंदु सरकार ने कम समय में ही त्वरित गति से अपने कदमों द्वारा यह स्थापित कर दिया कि राज्य किसी मजहब या पंथ विशेष या पार्टी नेताओं या समर्थकों लिए नहीं बल्कि सबके हित में काम करेगा, खजाने का धन किसी पंथ के तुष्टिकरण के लिए नहीं बल्कि उपयुक्त पात्रों के कल्याण पर खर्च होगा, शासन कानून और विधान के अनुसार चलेगा, प्राथमिकता आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा विकास होगा एवं पहले जो निहित स्वार्थी तत्व इसके रास्ते में आए, सत्ता का दुरुपयोग किया उन सबके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

हमें चैन से जीने दीजिए

एक अपील

ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं।

भारत के सभी राजनीतिक दलों, संघों, परिषदों, सम्प्रदायों, सभाओं, लीगों सहित सभी जात-पांत और कौम के नाम पर बनी सामाजिक संस्थाओं से सविनय निवेदन है कि हम भारत के लोग हिन्दू-मुसलमान के विभेदकारी नाम-जाप का कनफोड़ शोर सुन-सुन कर ऊब गये हैं और यह बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कृपया इसे बन्द कीजिए।

भारत के हिन्दू-मुसलमान आपस में एक-दूसरे के सुख-दुख में सहयोगी होकर अपनी गुजर-बसर कर रहे हैं। उन्हें अगर आपस में कोई शिकायत होती है तो वे खुद ही सुलझा लिया करते हैं। उन्हें कोई हिन्दू-मुस्लिमों की साम्प्रदायिक, राजनीतिक और मज़हबी पंचायतें नहीं चाहिए। यह रिश्ता सदियों से जुड़ा है और उसे किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। कोई लाख चतुराई करे, वह टूटेगा ही नहीं।

भारत में हिन्दू-मुसलमान के नाम पर बने और उनके बीच विभेद पैदा करने वाले संगठनों की उम्र तो करीब सौ बरस के आसपास की है और कुछ तो सौ साल से भी ज़्यादा के हो गये हैं। वे अब तक इस बड़ी इन्सानी बिरादरी को एक-दूसरे से दूर करने में विफल ही हुए हैं। हमारा भाईचारा अमिट है। अब इन विभेदकारी संगठनों को ही देश हित में अपनी भूल-गलतियों और विफलताओं पर गहन पश्चाताप करके अपने राजनीतिक प्रपंच और मज़हबी पाखण्ड को त्याग देना चाहिए।

हम भारत के लोग प्रार्थना करते हैं कि देश के सभी विभाजनकारी राजनीतिक और मज़हबी कुटिल मन बंधुता के लोकतांत्रिक बोध से भर उठें। वे अपनी शक्ति और साधन आपसी साहचर्य और समृद्धि की तरफ़ मोड़ दें। भारत की मनीषा ने सदियों के तप के बाद सबके जीवन के परस्पर आश्रय में उदारता के मूल्य को पहचानकर महान सभ्यता को गढ़ा है। हम भारत के लोग इस मूल्य को अपने जीवन में बचाकर एक उदाहरण के रूप में इस धरती पर जीवन्त बने रहना चाहते हैं।

भारत के प्रज्ञावान दृष्टा यह बात भली प्रकार समझा गये हैं कि पूरी सृष्टि में सबके प्राणों की एकता है और उसे सब अपनी-अपनी रूह के अहसास में पहचान सकते हैं। हम अनेक में प्राणों की एकता साधकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। इसके लिए आत्मिक रूप से प्रेम का पंथ सदियों से प्रस्तावित हैं जिसे अपनाकर बहुधर्मी जन मैत्रीपूर्ण संवाद के बीच जीवन जीने के उपाय करते ही रहते हैं।

अगर अपनी ही विफलताओं के कारण उपजे अन्याय का प्रतिकार भी करना पड़े तो वह आपसी मैत्री से ही किया जा सकता है। आत्मभाव को प्राप्त होकर अन्याय के प्रतिकार में कोई शत्रु सामने नहीं होता। सब एक-दूसरे का सामना मित्रवत ही करते हैं। इस पद्धति को अपनाने से पराजय किसी की नहीं होती, सिर्फ़ सबके साथ बने रहने के दीर्घकालीन रास्ते निकलते हैं।

देश में लोकमत परिष्कार और राष्ट्र निर्माण के दावे करने वाले स्वयंसेवी संगठन चल रहे हैं पर इनके रहते राजनीति जीवन को अराजक भीड़ में बदल रही है। धार्मिकता के मार्ग पर पाखण्ड का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। नये बाजारों में भटकता विषयासक्त जीवन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने आपको भूलकर जी रहा है। उदारचरित सभ्यता में कामुकता और क्रूरता बढ़ रही है।

राजनीतिक उद्देश्यों वाले स्वयंभू उद्धारक संगठनों की विफलता का मुख्य कारण ही यह है कि ये संगठन आदमी को किसी एक साँचे में ढालने की ज़िद बाँधे हुए हैं। जो इस साँचे में ढलने से इंकार करे उसे इनके परिकल्पित देश-काल में जगह ही नहीं है। इन संगठनों में ज़्यादातर अतीतजीवी ही हैं। उन्हें आदमी के उस बहुरंगी स्वभाव का सामना करना नहीं आता जो जन्मजात रूप से वर्तमान है। ये संगठन क्यों नहीं मान पाते कि आदमी के स्वभाव को किसी राजनीतिक सत्ता के द्वारा हठपूर्वक बदलना संभव नहीं। स्वयं ईश्वर की सत्ता के द्वारा भी नहीं। हर आदमी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने स्वभाव से बरतता है।

लोकतंत्र की अवधारणा में यह भावना निहित है कि वे कौन से आत्मीय उपाय होंगे जिनके करने से किसी देश में जीवन बिताने वाले विभिन्न स्वभाव के बहुविश्वासी आदमी अपने-अपने स्वभावों की पहचान करके परस्पर आश्रय में अपने संयम की नीति बना सकें। उन्हें किसी केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था की ज़रूरत ही न रहे। सब मिलकर अपना स्थानीय स्वराज्य गढ़कर अपनी प्रकृति से हिल-मिल कर गुजर-बसर करें। वे जीने के साधनों के पास रहें। साधन बचे रहें यही उनका साध्य हो।

ज्ञानी कह गये हैं कि दूसरों के दुःखों की सब ठेकेदारियां पापमय हैं। इन ठेकेदारियों ने आदमी को उसके पुरुषार्थ से डिगाया है। आदमी खुद अपना सामना कर सके, इस मार्ग से भटकाया है। व्यर्थ सेवा के ढोंग, मुफ़्तखोरी और कुतर्कों के बीच बहुरंगी जीवन कितना असहाय जान पड़ता है। विभेदकारी और स्वार्थपूर्ण बहुमत में विखण्डित राजनीति लोगों के मन में डर भर रही है। उन्हें भ्रमित करने वाली स्वार्थपूर्ण एकता में ही सुरक्षित रहने का नारा बुलन्द कर रही है। उसमें वह परमार्थ भावना ढूंढे नहीं मिल रही जो बहुरंगी जीवन को बंधुता के मार्ग पर चलाती है। जहाँ सब आपसी मैत्री अर्जित करने में समर्थ होते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

बीच में घुसने का सुख

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

भारतीय जनतंत्र में 'घुसपैठ' केवल सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि हमारे साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजनों की आत्मा में बसी है। कुछ विलक्षण प्रतिभाएं तो पैदा ही 'बीच में घुसने' के लिए होती हैं। इनका मूल मंत्र है 'जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ घुसे स्वयंभू कवि।'

किसी भी गरिमामय कार्यक्रम की मर्यादा का 'बंटाधार' करने में इन्हें महारत हासिल होती है। जब श्रोता मुख्य वक्ता के विचारों में डूबे होते हैं, तभी इन महाशय का पदार्पण होता है। ये 'बिन बुलाए मेहमान, और मंच पर ही सम्मान' वाली मुद्रा में होते हैं। इनका मानना है कि 'देर से आना' बड़े होने की पहली शर्त है। ये ऐसे चलते हैं जैसे हॉल की जमीन नहीं, बल्कि आयोजकों की छाती पर पैर रख रहे हों। इनके जूतों की चरमराहट यह घोषणा कर देती है कि असली 'तीर्थ' अब शुरू हुआ है।

इनका सबसे प्रिय शस्त्र है 'माइक'। माइक देखते ही इनके भीतर का सुषुप्त साहित्यकार अंगड़ाइयां लेने लगता है। संचालन कर रहे बेचारे उद्घोषक के हाथ से ये माइक ऐसे छीनते हैं, जैसे कोई 'अंधी पीसे कुत्ता खाए' वाली स्थिति हो। इसके बाद शुरू होती है 'भूमिका'। यह भूमिका इतनी लंबी होती है कि मुख्य विषय कहीं कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते-करते सो जाता है। वे कहेंगे, ष्मैं बोलना तो नहीं चाहता था, पर आयोजकों का प्रेम...और फिर अगले बीस मिनट तक वे यह बताते हैं कि वे क्या-क्या नहीं बोलना चाहते थे। 'थोथा चना बाजे' ।नाश् की तर्ज पर इनका भाषण श्रोताओं के धैर्य की खाल खींचने लगता है।

लेकिन इस 'बीच में घुसने के सुख' का असली रसास्वादन तो फोटो सेशन के समय होता है। किवदंती है कि पुराने जमाने में देवता आकाश से पुष्प वर्षा करते थे, पर आधुनिक युग के ये (साहित्यिक देवता) फ़ोटो के फ्रेम में वर्षा करते हैं। विशेषकर तब, जब मंच पर महिलाओं का समूह मौजूद हो। जैसे ही फोटोग्राफर 'स्माइल प्लीज' कहता है, ये महाशय 'मान न मान, मैं तेरा मेहमान' बनते हुए महिलाओं की कतार को चीरकर ठीक बीच में अवतरित होते हैं। वे ऐसे पोज देते हैं जैसे ग्रुप फोटो के असली 'दूल्हे' वही हों और बाकी सब महज 'बाराती'।

इनका चेहरा उस वक्त 'घी के दिए जलाने' जैसा चमक रहा होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे बीच में न घुसे, तो फोटो की गरिमा गिर जाएगी। वे जानते हैं कि 'सांप मरे न लाठी टूटे' वाली चतुराई से कैसे महिलाओं के बीच अपनी जगह बनानी है ताकि सोशल मीडिया पर उनकी 'लोकप्रियता' का झंडा गड़ा रहे। अंततः, बीच में घुसने का यह सुख वह अमृत है, जिसे पीकर ये जीव खुद को अमर मानते हैं। बेचारा दर्शक तो बस यही सोचता रह जाता है कि 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली बात यहाँ कब चरितार्थ होगी। आखिर इनका और माइक का 'चोली-दामन का साथ' जो ठहरा!

शहीदी दिवस पर विशेष

श्वेता गोयल

लेखक शिक्षक हैं।

बंदा सिंह बहादुर की अमर गाथा

बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी क्षेत्र के तच्छल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वे बचपन से ही साहसी, तेजस्वी और शारीरिक रूप से अत्यंत सक्षम थे। युवावस्था में एक ऐसी घटना घटी, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। शिकार के दौरान उनके तीर से एक गर्भवती हिरणी घायल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। हिरणी की पीड़ा और उसके गर्भस्थ शावक की मृत्यु ने उनके मन को झकझोर दिया। यह घटना उनके जीवन में गहन आत्ममंथन का कारण बनी। संसार की क्षणभंगुरता और हिंसा से विरक्त होकर उन्होंने गृहत्याग कर दिया और वैराग्य का मार्ग अपनाया। वे माधोदास बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अनेक तीर्थस्थलों की यात्राएं की, योग और साधना का अभ्यास किया तथा अंततः महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित किया। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह साधु आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे प्रखर योद्धाओं में से एक बनेगा।

भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महानायक हुए हैं, जिनका जीवन केवल युद्धों और विजयों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जिन्होंने समाज की दिशा बदलने का भी कार्य किया। बंदा सिंह बहादुर ऐसे ही विलक्षण योद्धा, समाज सुधारक और क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की अजेयता के मिथक को तोड़ा, शोषितों को अधिकार दिलाए और न्याय तथा समानता पर आधारित शासन की स्थापना का प्रयास किया। उनका जीवन साहस, त्याग, आध्यात्मिकता और राष्ट्रधर्म के अद्भुत समन्वय का उदाहरण है। 9 जून 1716 को उनका बलिदान भारतीय इतिहास के उन अमर अध्यायों में दर्ज हुआ, जिसने आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी।

बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ-राजौरी क्षेत्र के तच्छल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वे बचपन से ही साहसी, तेजस्वी और शारीरिक रूप से अत्यंत सक्षम थे। युवावस्था में एक ऐसी घटना घटी, जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। शिकार के दौरान उनके तीर से एक गर्भवती हिरणी घायल हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। हिरणी की पीड़ा और उसके गर्भस्थ शावक की मृत्यु ने उनके मन को झकझोर दिया। यह घटना उनके जीवन में गहन आत्ममंथन का कारण बनी। संसार की क्षणभंगुरता और हिंसा से विरक्त होकर उन्होंने गृहत्याग कर दिया और वैराग्य का मार्ग अपनाया। वे माधोदास बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अनेक तीर्थस्थलों की यात्राएं की, योग और साधना का अभ्यास किया तथा अंततः महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के तट पर अपना आश्रम स्थापित किया। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह साधु आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे प्रखर योद्धाओं में से एक बनेगा। सन् 1708 में नांदेड़ में उनकी भेंट सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी से हुई। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय मुगल अत्याचारों के विरुद्ध संघर्षरत थे। उनके चारों पुत्रों का बलिदान हो चुका था और पंजाब में सिखों तथा आम जनता पर अत्याचार चरम पर थे। गुरु साहिब ने माधोदास को समझाया कि केवल व्यक्तिगत मोक्ष की साधना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष भी धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा से माधोदास ने संन्यास त्यागकर शस्त्र धारण किए और 'बंदा सिंह बहादुर' के रूप में एक नए जीवन का आरंभ किया। गुरु साहिब ने उन्हें पंजाब भेजा और धर्म, मानवता तथा न्याय की रक्षा का दायित्व सौंपा। बंदा सिंह ने इस दायित्व को अपना जीवन मिशन बना लिया। 1709 में पंजाब पहुंचते ही उन्होंने मुगल सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने सबसे पहले सोनीपत और कैथल जैसे क्षेत्रों में मुगल प्रशासन को चुनौती दी। उनकी सैन्य प्रतिभा, संगठन क्षमता और निर्भीक नेतृत्व ने शीघ्र ही किसानों, मजदूरों तथा पीड़ित जनता का समर्थन अर्जित कर लिया। कुछ ही समय में उनके नेतृत्व में हजारों लोगों की सेना तैयार हो गई।

बंदा सिंह बहादुर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक विजय 1710 में सरहिंद पर हुई। सरहिंद का नवाब वजीर खान वही व्यक्ति था, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों (साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह) को जीवित दीवार में चुनवाने का दोषी माना जाता है। चप्पड़ चिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर ने वजीर खान को पराजित कर उसका अंत कर दिया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी बल्कि न्याय और प्रतिरोध की ऐतिहासिक जीत थी। सरहिंद विजय के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जो कार्य किए, उन्होंने उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि महान समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। उस समय समाज सामंती शोषण और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त था। बंदा सिंह ने किसानों को भूमि का स्वामित्व प्रदान किया और जमींदारी शोषण को चुनौती दी। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने पहली बार उन लोगों को भूमि का अधिकार दिलाया, जो पीढ़ियों से केवल खेती करते थे लेकिन भूमि के मालिक नहीं थे। यह उस युग में एक क्रांतिकारी कदम था।

उनके शासन में जाति, जन्म और सामाजिक स्थिति की अपेक्षा योग्यता और निष्ठा को महत्व दिया गया। निम्न वर्गों के लोगों को प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पद दिए गए। इस प्रकार उन्होंने सामाजिक समानता की एक नई मिसाल प्रस्तुत की। यही कारण है कि वे केवल सिख इतिहास ही नहीं, भारत के सामाजिक न्याय आंदोलन के भी महत्वपूर्ण नायक माने जाते हैं। बंदा सिंह बहादुर ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सांस्कृतिक स्वाभिमान को भी महत्व दिया। उन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर सिक्के जारी किए। यह कदम मुगल सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्र शासन की उद्घोषणा था। उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और खालसा राज की नींव रखी। यह उत्तर भारत में मुगल प्रभुत्व को खुली चुनौती थी। उनकी बढ़ती शक्ति और लोकप्रियता से मुगल शासन अत्यंत चिंतित हो गया। मुगल बादशाह बहादुरशाह और बाद में फर्रूखसियर ने उनके विरुद्ध विशाल सैन्य अभियान चलाए। कई वर्षों तक संघर्ष जारी रहा। संसाधनों और सैनिकों की दृष्टि से मुगल सेना कहीं अधिक शक्तिशाली थी, फिर भी बंदा सिंह बहादुर ने अद्भुत साहस के साथ उनका मुकाबला किया। अंततः गुरदास नंगल के किले में लंबे घेरे के बाद भोजन और पानी की भारी कमी उत्पन्न हो गई। लगभग आठ महीने तक चले संघर्ष के पश्चात 17 दिसंबर 1715 को उन्हें उनके सैंकड़ों साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। बंदा सिंह बहादुर और उनके अनुयायियों को लोहे के पिंजरों में बंद करके दिल्ली लाया गया। रास्ते भर उन्हें अपमानित किया गया लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। दिल्ली में उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनके साथियों को एक-एक करके मृत्यु दंड दिया गया। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बंदा सिंह बहादुर पर धर्म परिवर्तन का भारी दबाव डाला गया लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों और विश्वास से समझौता करने से साफ इंकार कर दिया। कहा जाता है कि उनके सामने उनके पांच वर्षीय पुत्र अजय सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई किंतु उनका धैर्य और आत्मबल अडिग रहा। 9 जून 1716 को उन्हें अत्यंत क्रूर तरीके से शहीद कर दिया गया। उनकी आंखें निकाली गई, शरीर को यातनाएं दी गई और अंततः उनके अंग-भंग कर दिए गए लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने न तो धर्म छोड़ा और न ही आदर्शों से समझौता किया। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक बन गया कि सत्य, न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से भले पराजित हो जाए किंतु उसकी विचारधारा कभी पराजित नहीं होती।

बंदा सिंह बहादुर का जीवन केवल युद्ध और शहादत की कहानी नहीं है। वे आध्यात्मिकता से कर्मयोग की ओर बढ़ने वाले ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने दिखाया कि धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी है। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा प्रस्तुत की, वह अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। उनके बलिदान दिवस पर जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो केवल एक वीर योद्धा को श्रद्धांजलि नहीं देते बल्कि उस विचार को नमन करते हैं जिसने शोषितों को अधिकार, पीड़ितों को न्याय और समाज को समानता का संदेश दिया। बंदा सिंह बहादुर भारतीय इतिहास के उन अमर नायकों में हैं, जिनकी वीरता, त्याग और सामाजिक चेतना सदियों तक राष्ट्र को प्रेरित करती रहेगी।

पुस्तक समीक्षा

सुनील सक्सेना

समीक्षक

सूखे सावन: दबाई गई चीखों की कहानियां

हम जब उर्दू भाषा की बात करते हैं तो इसमें अभी भी ऐसा बहुत कुछ शेष है जो हिंदी पाठकों तक नहीं पहुंचा है । अनुवाद ही ऐसा जरिया है जो हमें दीगर भाषाओं के साहित्य संसार में प्रवेश करने का अवसर देता है। रेख्ता पब्लिकेशन ने हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के बीच पुल बांधने का काम करते हुए उर्दू के कई ऐसे रचनाकारों की कृतियों को हिंदी में उपलब्ध कराने का काम किया है, जो मुख्य धारा के साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाई। रेख्ता पब्लिकेशन से प्रकाशित 'सूखे सावन' कहानी संग्रह में उर्दू के उन अफ़सानानिगारों की कहानियां हैं जिन्होंने जिंस या यौनिकता जैसे विषय पर अपनी कलम चलाई है, जिसे पितृसत्तात्मक समाज ने नैतिकता के नाम पर वर्जित कर रखा है। पुरूषों ने शर्म, तहजीब, इज्जत की आड़ लेकर स्त्री की यौनिक ख्वाहिशों, दैहिक जरूरतों को जब-तब दबाया और कभी किसी औरत ने इसका खुलकर इजहार किया भी तो बेशर्म, बेहया, बदचलन कहकर उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया।

ऐसा कहा जाता है कि किसी भी भाषा के साहित्य की समृद्धि के लिए ये जरूरी है कि दूसरी भाषाओं में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है इस पर रचनाकारों की निगाह रहे । एक लेखक के नाते ये जरूरी है कि उसकी अन्य भाषाओं के गलियारों में आवाजाही बने रहे ।

मुरकामी भी कहते हैं कि अगर आप वही पढ़ रहे हैं जो सब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ उतना ही सोच पाएंगे जितना सब सोच रहे हैं या जैसा सोच रहे हैं। तो 'समथिंग डिफ्रेंट' रचने के लिए, गढ़ने के लिए हमें अपनी भाषा की चौहद्दी पार करके दूसरी भाषाओं के घर में भी डेरा डालना होगा । उनसे राब्ता रखना होगा ।

हम जब उर्दू भाषा की बात करते हैं तो इसमें अभी भी ऐसा बहुत कुछ शेष है जो हिंदी पाठकों तक नहीं पहुंचा है । अनुवाद ही ऐसा जरिया है जो हमें दीगर भाषाओं के साहित्य संसार में प्रवेश करने का अवसर देता है । रेख्ता पब्लिकेशन ने हिंदी और उर्दू दो भाषाओं के बीच पुल बांधने का काम करते हुए उर्दू के कई ऐसे रचनाकारों की कृतियों को हिंदी में उपलब्ध कराने का काम किया है, जो मुख्य धारा के साहित्य का हिस्सा नहीं बन पाई ।

रेख्ता पब्लिकेशन से प्रकाशित 'सूखे सावन' कहानी संग्रह में उर्दू के उन अफ़सानानिगारों की कहानियां हैं जिन्होंने जिंस या यौनिकता जैसे विषय पर अपनी कलम चलाई है, जिसे पितृसत्तात्मक समाज ने नैतिकता के नाम पर वर्जित कर रखा है । पुरूषों ने शर्म, तहजीब, इज्जत की आड़ लेकर स्त्री की यौनिक ख्वाहिशों, दैहिक जरूरतों को जब-तब दबाया और कभी किसी औरत ने इसका खुलकर इजहार किया भी तो बेशर्म, बेहया, बदचलन कहकर उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया ।

यूं तो कहा जाता है कि साहित्य का काम है कि परंपराओं, रूढ़ियों से टकराना, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, पर ये साहस कम ही रचनाकार कर पाते हैं ।

मंटो और इस्मत चुगताई ने समाज के ठेकेदारों की आंख में आंख डालकर सच कहने का साहस दिखाया था । यौनिकता, तवायफों जैसे परहेजी विषयों को आधार बनाकार जब इन्होंने कुछ लिखा तो बुद्धिजीवी समाज ने उसे अश्लील और गंदा साहित्य करार कर दोनों को कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया । उनका जुर्म मात्र इतना था कि समाज में कालीन के अंदर छिपी उस गंदगी को सरेआम कर दिया था जिसकी चर्चा तो छोड़िए फुसफुसाहट मात्र से सफेदपोश सरमायेदार घूंघट डालकर आज भी बच निकलते हैं ।

'सूखे सावन' कहानी संग्रह की सभी कहानियों में नाजुक समाजी घटनाओं की नब्ज टटोलने की कामयाब कोशिश की गई है। घरों में मर्दों की दबंगयाई, विवाहेत्तर संबंध, बेवाफाई, स्त्री के दमन जैसे मसलों की पृष्ठभूमि पर रची इन कुल दस कहानियों में प्रत्येक कहानीकार ने अपनी बात पुरजोर ढंग से उठाई है ।

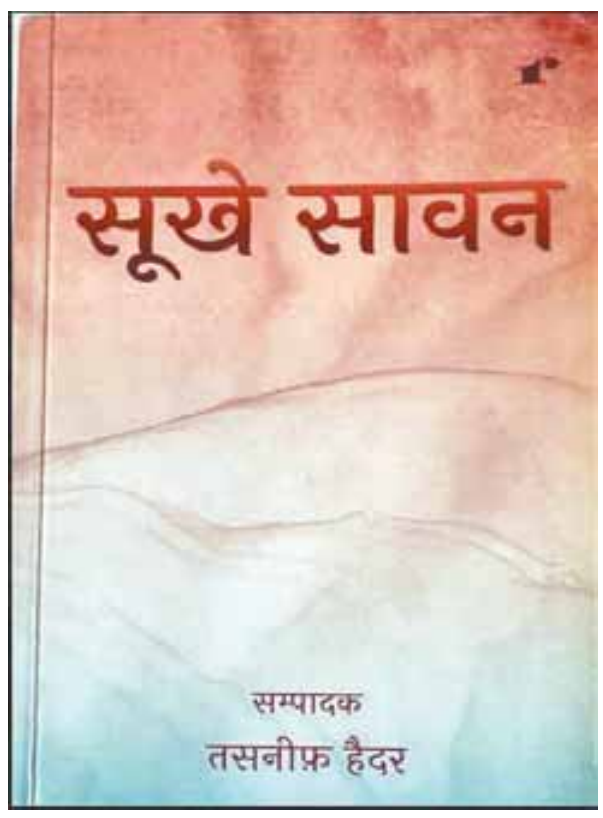

कहानी संग्रह की एक कहानी बड़ी दिलचस्प बन पड़ी है जो पूरी किताब को पढ़ लेने के बाद भी हॉन्ट करती रहती है । 'लोहे का कमरबंद' । इस कहानी के लेखक हैं रामलाल, जिनका जन्म पाकिस्तान के मियानवाली में हुआ था और विभाजन के बाद वे लखनऊ आ गए थे ।

कहानी एक व्यापारी की है जो तिजारत के सिलसिले में दूसरे देश जाता है । उसकी पत्नी निहायत ही खूबसूरत है । परदेस जाते समय वो पत्नी को समाज में विचर रहे बदनियत रखने वाले पुरूषों का हवाला देते हुए, उनसे सुरक्षित रखने के लिए, पत्नी की कमर में लोहे का कमरबंद बांध कर ताला जड़ देता है और चाबी अपने साथ ले जाता है । अविश्वास की पराकाष्ठा। पति विदेश से कब लौटेगा कुछ पता नहीं ।

पति के परदेस जाने के बाद पत्नी का जीवन उस लोहे के कमरबंद को पहने हुए किस तरह गुजरता है, निरंतर यातना और संत्रास के बीच जीवन जीती असहाय औरत की करूणामय बानगी है ये कहानी । अंत में उस कमरबंद पहने स्त्री का क्या हश्र होता है, इसका रोचक तानाबाना कहानीकार ने बुना है जो पाठक को अंत तक बांधे रखता है । औरत को इंसानियत के दूसरे दर्जे पर रखने वाले हमारे समाज के मुंह पर ये कहानी जबरदस्त तमाचा है ।

अवसरवादी समाज ने नैतिकता को तौलने के लिए तराजू तो एक रखी है लेकिन बटखरे अपने हिसाब से बना रखे हैं । बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए मोहम्मद हसन की कहानी 'हरामजादा बुद्धू' ऐसे ही व्यभिचारी, जिस्मखोर इंसान की कहानी है जो बिरादरी में नेकदिल इंसान के तौर पर जाना जाता है ।

वो अपने दोस्त की मौत पर उसकी पत्नी और इकलौती बेटी से मिलने आता है । मरहूम के गहरे दोस्त होने का वास्ता देकर उनके घर में पैठ बनाता है। कपड़े -लत्ते, खाने-पीने के खर्चे उठाता है । मां-बेटी का विश्वास अर्जित कर लेता है ।

एक दिन मौका मिलते ही दोस्त की जवान बेटी से जब वो बलात शारीरिक संबंध बनाता है तो लड़की कहती है- ये आप क्या कर रहे हैं, अब्बा हैं आप मेरे । वो गलीच इंसान कहता है- तुम कोई मेरे नुत्फ़े से पैदा बेटी थोड़े हो । ज़बान से बेटी कह देने से खून तो एक नहीं हो जाता । आज के समाज में धूलधूसरित होती मानवीय संवेदनाएं और रिश्तों की उड़ती धज्जियों पर शर्मसार कर देने वाली कहानी है 'हरामजादा बुद्धू'। कहानी पाठक को अपनी बगले झांकने पर विवश कर देती है । ग्लानी पैदा हो जाती है कि वो ऐसे रीढ़ विहीन समाज का एक हिस्सा है ।

संग्रह की कहानियां इस बात की तस्दीक़ करती हैं कि उर्दू ज़बान सिर्फ शेरो-शायरी तक ही महदूद नहीं है, उसकी बादशाहत कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में भी उतनी ही शान- बान और मजबूती से कायम है ।

किसी भी संग्रह को पठनीय बनाने में रचनाओं का चयन महत्वपूर्ण होता है। ये उस संग्रह के सम्पादक के विवेक पर निर्भर है कि वो किसी एक विषय वस्तु पर लिखी तमाम रचनाओं का कितनी गहराई से अध्ययन करता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कौनसी कहानी चयन के योग्य है ।

तसनीफ़ हैदर इस कहानी संग्रह के सम्पादक हैं। वे स्वयं भी उम्दा कहानीकार, शाइर हैं । इस संग्रह में उनके द्वारा चुनी हुई कहानियों में उनकी मेहनत, परिश्रम साफ नजर आता है । यही वजह है कि ये कहानी संग्रह कहानियों का मोंटाज भर नहीं हैं बल्कि नारी की दबी हुई चीखों का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसे अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए ।

पुस्तक - सूखे सावन
सम्पादक - तसनीफ हैदर
प्रकाशक - रेख्ता प्रकाशन
मूल्य - 299/-

सामयिक

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

एमआरपी निर्धारण में पारदर्शिता की मांग

भारत में उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा को जनआंदोलन का स्वरूप देने वाली प्रमुख संस्थाओं में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। वर्ष 1974 में स्थापित यह संगठन पिछले पांच दशकों से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा, जागरूकता और उपभोक्ता हितैषी नीतियों के निर्माण के लिए सतत कार्य कर रहा है। बदलते आर्थिक परिवेश, उदारीकरण और बाजारवाद के दौर में जहां उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं मूल्य निर्धारण की जटिलताओं ने ग्राहकों के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं।

इन्हीं चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है एमआरपी (Ma&imum Retail Price) अर्थात् अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण। आज बाजार में उपलब्ध अनेक उत्पादों पर अंकित एमआरपी और उनकी वास्तविक उत्पादन लागत के बीच भारी अंतर देखने को मिलता है। कई मामलों में उत्पादन लागत, करों, परिवहन एवं उचित लाभांश को जोड़ने के बाद भी एमआरपी कई गुना अधिक निर्धारित की जाती है। परिणामस्वरूप ग्राहक यह समझ नहीं पाता कि वह किसी वस्तु का उचित मूल्य चुका रहा है या नहीं।

ग्राहक संगठनों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में एमआरपी निर्धारण के लिए पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। उत्पादक कंपनियां, वितरक और विपणन तंत्र अपनी-अपनी लागत और लाभ को जोड़कर ऐसा मूल्य निर्धारित कर देते हैं, जिसकी वास्तविकता से सामान्य उपभोक्ता अनभिज्ञ रहता है। विशेष रूप से दवाइयों, सौंदर्य प्रसाधनों, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा कुछ उपभोक्ता उत्पादों में लागत और एमआरपी के बीच अत्यधिक अंतर की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का मत है कि एमआरपी केवल एक अंकित मूल्य न होकर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लागत, कर, वितरण व्यय और लाभ का तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार स्पष्ट हो।

संगठन की मांग है कि केंद्र सरकार एक समग्र एवं प्रभावी कानून बनाए, जिसमें एमआरपी निर्धारण के वैज्ञानिक मानक तय किए जाएं तथा उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार मिले कि किसी उत्पाद की कीमत किन तत्वों के आधार पर निर्धारित की गई है।

इन्हीं मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन 12 जून 2026 को प्रातः 9 बजे, जंतर मंतर पर आयोजित होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से ग्राहक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञ और आम नागरिक भाग लेंगे। प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार और नीति-निर्माताओं का ध्यान एमआरपी निर्धारण की विसंगतियों की ओर आकर्षित करना तथा उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ठोस कानूनी व्यवस्था की मांग करना है।

संगठन का कहना है कि जब देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून और विभिन्न नियामक व्यवस्थाएं लागू हैं, तब मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी समय की मांग है। ग्राहक केवल वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि ग्राहक के साथ मूल्य निर्धारण के स्तर पर ही असमानता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो बाजार की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि उपभोक्ता अधिकारों को केवल शिकायत निवारण तक सीमित न रखकर आर्थिक न्याय के व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए। एमआरपी निर्धारण में पारदर्शिता, उचित लाभ की सीमा, लागत संबंधी जानकारी की उपलब्धता तथा प्रभावी निगरानी व्यवस्था जैसे विषयों पर गंभीर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का यह अभियान केवल किसी एक संगठन की मांग नहीं, बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं की उस अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वे निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बाजार व्यवस्था चाहते हैं। यदि ग्राहक को सही जानकारी और उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके, तो यह न केवल उपभोक्ता हितों की रक्षा करेगा बल्कि बाजार में विश्वास और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी मजबूत बनाएगा।

राजा भोज की पावन धरा ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी, धार का मान बढ़ाने वाले रत्न हुए सम्मानित

रोटरी क्लब ऑफ धार सेंट्रल का गवर्नर ऑफिशियल विजिट एवं सम्मान समारोह यादगार बन गया

(राजेश शर्मा, धार)

राजा भोज की पावन धरा धारा नगरी भव्य - गरिमामय ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बनी। बरसों-बरस स्मृतियों में अंकित रहने वाली यह शाम भव्य और यादगार बन गयी। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के गवर्नर, रोटेरियन, प्रशासनिक अधिकारी, ख्यातनाम चिकित्सक, समाजसेवी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, साहित्यकार, समाजसेवी और विशिष्ट हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम को गरिमामय स्वरूप प्रदान कर रही थी। देश और दुनिया में धार की यशोगाथा और मान बढ़ाने वाले रत्नों के सम्मान से यह कार्यक्रम भव्य बन गया। इस अनूठे और भव्य कार्यक्रम की सूत्रधार (आयोजक) रोटरी क्लब ऑफ धार सेंट्रल की गवर्नर ऑफिशियल विजिट एवं सम्मान समारोह सचमुच यादगार बन गया।

रोटरी क्लब धार सेंट्रल स्थापना वर्ष 2008 से निरंतर समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानवीय कार्यों के माध्यम से उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटे. सुशील मल्होत्रा उपस्थित रहे।अध्यक्षता धार की प्रतिभाशाली बेटी एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ हरदा सुश्री अंजलि जोसेफ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटे. संस्कार कोठारी एवं पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटे. अनीश मलिक उपस्थित रहे। मंचासीन रोटरी क्लब धार सेंट्रल के अध्यक्ष प्रख्यात दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ रोटे. डॉ. मनीष कुमार सिंह, सचिव रोटे. विमल कुमार

सिंह, संस्थापक अध्यक्ष रोटे. अरुण वर्मा, कार्यक्रम अध्यक्ष रोटे. डॉ. अजेश माइकल उपस्थित थे।

रोटे. डॉ. सिल्वी वर्मा सिंह ने वूमेन आइकन अवार्ड की अवधारणा एवं महत्व पर प्रकाश डाला। रोटे. डॉ. मनीष कुमार सिंह ने अंतरराष्ट्रीय वोकेशनल सर्विस अवार्ड के बारे में जानकारी दी, रोटे. डॉ. शशांक तिलवणकर ने टीचर एक्सीलेंस अवार्ड एवं नेशन बिल्डिंग अवार्ड की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। संस्थापक अध्यक्ष रोटे. अरुण वर्मा ने प्रशस्ति पत्रों का वाचन किया। संचालन रोटे. डॉ. शशांक तिलवणकर द्वारा किया गया।

खास-खास

विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 85 व्यक्तित्वों को निम्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया

● टीचर एक्सीलेंस अवॉर्ड ● नेशन बिल्डिंग अवॉर्ड ● वोकेशनल सर्विस अवॉर्ड ● वूमेन आइकन अवॉर्ड ● धार रत्न अवॉर्ड।

● आगामी वर्ष 2026-27 के अध्यक्ष रोटे. विमल कुमार सिंह, मानद सचिव रोटे. डॉ. सिल्वी वर्मा सिंह तथा नवगठित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट रोटे. संस्कार कोठारी द्वारा शपथ दिलाई।

धार रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाली हस्तियां

धार रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाली हस्तियों में डॉ. चौधरी, डॉ. उमेश मित्तल, डॉ. एम.एम. महाजन, धार की बेटी एवं आईएएस अधिकारी सुश्री अंजलि जोसेफ अंतरराष्ट्रीय कवि संदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार डावर, डॉ. राघवेंद्र तिवारी, डॉ. प्रमिला गुप्ता, डॉ. आशुतोष उपाध्याय, डॉ. ऋचा उपाध्याय, पवन जैन, प्रोफे. कविता पॉल, धार इन न्यूज़ के प्रबंध संपादक धीरेंद्र दिघे, थाना प्रभारी कोतवाली दीपक सिंह चौहान, थाना प्रभारी राजगढ़ समीर पाटीदार।

रोटरी क्लब धार सेंट्रल 18 वर्षों से प्रदेश में रोटरी की गौरवशाली पहचान बनाए हुए है

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटे. सुशील मल्होत्रा ने क्लब की सेवा गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि रोटरी क्लब धार सेंट्रल के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित एवं समाजहितैषी व्यक्तित्व हैं। चिकित्सक, प्राध्यापक, उद्योगपति, व्यवसायी एवं समाजसेवियों से युक्त यह क्लब विगत 18 वर्षों से प्रदेश में रोटरी की गौरवशाली पहचान बनाए हुए है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष रोटेरियन अरुण वर्मा ने क्लब की स्थायी परियोजनाओं, विशेष रूप से डीआरपी स्थित फिजियोथेरेपी सेंटर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं तथा मेडिकल कैंपों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया। रोटे. सचिन बाफना, प्रफुल्ल जैन, अंजलि पवार, दिलीप मेघानी, एड. धर्मेश अग्रवाल, एड. आरती अग्रवाल, डॉ. ऋषि तिवारी, ध्रुव जोशी, ममता जोशी, पूर्व अध्यक्ष रोटे. अलका वर्मा, डॉ. लीना माइकल, डॉ. अजेश माइकल, डॉ. प्रदीप पाल, प्रो. कविता पॉल सहित रोटेरियन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सोयाबीन से मोहभंग हुआ, मक्का की तरफ किसानों का बढ़ा रूझान

जिले में 540 हेक्टेयर बढ़ा खरीफ सीजन का रकबा

एस. द्विवेदी, बैतूल। कृषि विभाग ने खरीफ का रकबा तय कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में 4 लाख 56 हजार 050 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की जायेगी। पिछले साल जिले में 4 लाख 55 हजार 510 हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई थी, जबकि इस साल विभाग द्वारा जो रकबा निर्धारित किया गया है, उसमें 540 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की है। विभाग ने इस वर्ष जिले में मक्का की बोवनी का लक्ष्य 3 लाख 1 हजार 500 हेक्टेयर निर्धारित किया है, जबकि सोयाबीन का लक्ष्य मात्र 95 हजार हेक्टेयर रखा है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार खरीफ वर्ष 2025 में जिले में मक्का का रकबा 3 लाख 93 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2026 में बढक़र 3 लाख 1 हजार 500 हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं सोयाबीन का रकबा 93 हजार 846 हेक्टेयर से बढ़ाकर 95 हजार हेक्टेयर प्रस्तावित किया है। बता दे कि खरीफ फसल की बुआई के लिए किसानों ने खेत बनाना शुरू कर दिया है। कहीं-कहीं भी किसानों ने बुआई के लिए खेतों को तैयार करने और खाद-बीज की व्यवस्था भी कर ली है। अब किसान बारिश का इंतजार कर रहे है कि जैसे ही मानसून सक्रिय होगा, वह बुआई कार्य प्रारंभ कर देगें। किसानों का कहना है कि अभी से योजना बना रहे है कि कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल की बुआई करे।

सोयाबीन की तुलना में तीन गुना बढ़ा मक्का का रकबा- मक्का का क्षेत्रफल सोयाबीन की तुलना में तीन गुना अधिक है। जिले में मक्का का रकबा सोयाबीन से लगभग 2 लाख 6 हजार 500 हेक्टेयर अधिक है। हालांकि कभी खरीफ सीजन में किसानों की पहली पसंद सोयाबीन रहती थी, लेकिन अब सोयाबीन की जगह मक्का ने ले ली है। यहीं वजह है कि मक्का तेजी से प्रमुख फसल के रूप में उभरकर सामने आया है। मक्के का रकबा बढ़ने के पीछे एक कारण यह भी है कि मक्का से पशु आहार भी प्राप्त होता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है। मक्का की मजबूत जड़ें मिट्टी की संरचना सुधारने में भी सहायक मानी जाती हैं, जिससे भूमि की उर्वरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

इन फसलों का बढ़ा रकबा- जिले में जहां खरीफ सीजन की कुछ फसलों का रकबा बढ़ाया है, वहीं कुछ फसलों का रकबा कम भी किया है। इस साल धान का रकबा 42.872 से बढ़ाकर 44.000 कर दिया है, वहीं कोदोकुटकी का रकबा पिछले साल 0.639 हेक्टेयर था, वहीं इस साल कोदो-कुटकी का रकबा बढ़ाकर 1.000 हेक्टेयर किया है। इसी प्रकार उड़द, मूंग, योग दलहन, तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन, कपास का रकबा बढ़ाया है, वहीं ज्वार के रकबे में कमी की है। ज्वार का रकबा पिछले साल 5.234 हेक्टेयर था, इस साल 1.500 हेक्टेयर कर दिया है। कुल मिलाकर इस साल कृषि विभाग ने 540 हेक्टेयर रकबे में बढ़ोत्तरी की है।

इनका कहना है -

इस साल खरीफ सीजन के रकबे में 540 हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी की है। यह सही है कि अब किसान सोयाबीन के स्थान पर मक्का को ज्यादा महत्व देने लगे है। जिसके कारण मक्के का रकबा साल दर साल बढ़ रहा है।

- सुरेन्द्र परते,
एडीए, कृषि विभाग, बैतूल

किसानों का सोयाबीन से इसलिए हुआ मोहभंग...

जानकारों के मुताबिक एक समय बैतूल जिले की पहचान सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र के रूप में होती थी। पिछले कुछ वर्षों में अनियमित बारिश, अतिवृष्टि, जलभराव, सूखे की स्थिति और विभिन्न कीट एवं रोगों के बढ़ते प्रकोप ने किसानों को आर्थिक रूप से प्रभावित किया। लगातार नुकसान झेलने के बाद किसानों ने धीरे-धीरे फसल चक्र में बदलाव करना शुरू किया और मक्का की ओर रुख किया। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि मक्का की लोकप्रियता बढ़ने के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। मक्का की फसल सोयाबीन की तुलना में जलजमाव और सूखे जैसी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से सहन कर लेती है। इसके अलावा इसमें रोगों का प्रकोप अपेक्षाकृत कम होता है, जिससे कीटनाशकों का खर्च घटता है। मक्का की मांग लगातार बनी रहने से किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना भी रहती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मक्का की प्रति एकड़ उत्पादकता सोयाबीन की तुलना में अधिक होती है।

खरीफ सीजन से पहले कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन, चोपना में निलय डागा ने उठाए किसानों के मुद्दे

खाद, बीज और कृषि ऋण जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भटक रहा वनांचल क्षेत्र का किसान

बैतूल। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही बैतूल के वनांचल क्षेत्र में किसानों की परेशानियां खुलकर सामने आ गई हैं। खेतों में बुवाई का समय आ चुका है, लेकिन कई किसान खाद, बीज और कृषि ऋण के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। चोपना क्षेत्र में किसानों की इसी पीड़ा को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सडक़ पर उतर आई और धरना-प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निलय विनोद डागा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सहकारी समिति में पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध नहीं है, जबकि वन अधिकार पट्टाधारी एवं अन्य पात्र किसानों को कृषि ऋण और खाद वितरण में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो हजारों किसानों की खरीफ फसल प्रभावित हो सकती है और इसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ेगा। गौरतलब है कि चोपना क्षेत्र में जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर खाद-बीज की कमी, कृषि ऋण वितरण में आ रही परेशानियों तथा वन अधिकार पट्टाधारी किसानों के साथ हो रहे कथित भेदभाव के मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि खरीफ सीजन शुरू होने के बावजूद किसानों को जरूरी कृषि संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक निलय विनोद डागा के नेतृत्व में सोमवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के चोपना एवं आसपास के वनांचल क्षेत्रों के किसान खाद, बीज और कृषि ऋण की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। समय पर संसाधन नहीं मिलने से खेती और किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

तत्काल राहत की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि चोपना सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराया जाए तथा वन अधिकार पट्टाधारी एवं अन्य पात्र किसानों को बिना किसी भेदभाव के कृषि ऋण प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। निलय डागा ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर त्वरित कार्रवाई करने और क्षेत्र के हजारों किसानों को राहत दिलाने की मांग की। धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय डागा, जनपद पंचायत घोडाडोंगरी अध्यक्ष राहुल उइके, विधानसभा प्रभारी एवं कांग्रेस प्रवक्ता लवलेष बब्बा राठौर, चोपना ब्लाक प्रभारी एवं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह राजपूत, ब्लाक अध्यक्ष निताईकर, भोला कांति, संजय सालवे सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

वनाधिकार पट्टाधारी किसानों का मुद्दा भी उठाया- ज्ञापन में विशेष रूप से वन अधिकार पट्टाधारी किसानों की समस्याओं का उल्लेख किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वन अधिकार पट्टा प्राप्त किसानों को खाद वितरण और कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अनावश्यक बाधाएं खड़ी की जा रही हैं। इससे पात्र किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं और खेती की तैयारी प्रभावित हो रही है।

खाद-बीज और ऋण संकट से बढ़ी चिंता- कांग्रेस ने कहा कि चोपना सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज नहीं मिल पा रहा है। वहीं पात्र किसानों को कृषि ऋण नहीं मिलने से खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। किसानों को बार-बार सहकारी समिति के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। खरीफ सीजन के दौरान यह स्थिति बनी रही तो फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है।

तुलसी पौधों से राम के संस्कारों का बीजारोपण प्रारंभ

भगवान राम को 1100 पौधे अर्पित कर राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की स्मृति में 'ग्राम दर्शन-राम दर्शन' अभियान की शुरुआत मांडू से हुई

धार। राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की स्मृति में 'ग्राम दर्शन-राम दर्शन' अभियान की औपचारिक शुरुआत मध्य प्रदेश के धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में भगवान राम को 1100 पौधे अर्पित कर शुरू हुआ। सोमवार को मांडू के चतुर्भुज राम मंदिर के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर डॉ. नरसिंह दास महाराज और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धर्म जागरण के मालवा प्रांत अधिकारी अभिषेक गुप्ता एवं आयोजक नवनीत जैन ने इस अभियान का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर 51 हजार तुलसी के पौधों का पूजन कर उन्हें वितरण हेतु रवाना किया गया। अभियान की शुरुआत संत-महात्माओं, आचार्यों और पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्पांजलि और महाआरती के साथ हुई। भगवान शालिग्राम का विशेष औषधीय अभिषेक पूजन-अर्चन भी किया गया।

आयोजन की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि यह गांवों में आयोजित एक अनूठा पर्यावरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस के माध्यम से गांवों में संस्कार, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, जिसमें तुलसी के पौधे बांटना शामिल है। उन्होंने तुलसी को लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रोगों से दूर रखने के लिए रामबाण बताया। महामंडलेश्वर डॉ. नरसिंह दास महाराज ने कहा कि तुलसी का पौधा घर को मंदिर का रूप देने के साथ-साथ शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। सनातन संस्कृति में 'घर-घर तुलसी' का होना अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया है। यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों का भंडार है जो घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और आरोग्यता लाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसके पत्तों का नित्य सेवन सर्दी-जुकाम और रोगों से लड़ने में सहायक होता है।

ग्राम दर्शन-राम दर्शन के आयोजक नवनीत जैन ने कहा कि तुलसी को देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी हरी-भरी होती है, वहां सदैव धन-धान्य और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और वास्तु दोषों को दूर करता है।

यह 'ग्राम दर्शन-राम दर्शन' अभियान पांच दिवसीय है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पांच परिवर्तन के सिद्धांतों को जनमानस में स्थापित कर 51 हजार तुलसी के पौधे वितरित कर पर्यावरण और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है। वही हमारे द्वारा पांच परिवर्तन के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर ग्राम दर्शन राम दर्शन अभियान के पांच मुख्य बिंदु है जिसमें पहला बिंदु है समरसता का आयोजन होगा दूसरा बिंदु है कुटुंब प्रबोधन सयुक्त परिवार के साथ मिलकर चर्चा करना, वही तीसरा बिंदु है स्वदेशी जिसमें हम ग्रामीणों को स्थानीय रोजगार उन्नयन करने वाले और समाज सेवकों का सम्मान होगा चौथा नागरिक अनुशासन को प्रभावी बनाने के लिए के लिए ओर युवाओं में जागृति हेतु कार्य किया जाएगा पांचवा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्र बनाया जाएगा साथ ही दहेज मुक्त और नशामुक्त परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा।

बल खाती स्पीड से चलती हैं बसें, बाइक सवार को मारी टक्कर

सोहागपुर। नर्मदापुरम से पिपरिया तक लगभग सभी बसें बंद खाती स्पीड से चलती रहती है बसें। बसों के वाहन चालकों को अहसास नहीं होता कि किसी राहगीर की टक्कर से बाइक सवार या पैदल चलने वालों के साथ दुर्घटना हो सकती है। इससे व्यक्ति घायल या उसकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कानून भी इतना इतना लचीला है कि टक्कर मारे वाला वाहन चालक ऐनकेन तरीके से बच निकलता है। आज दिन देखा जाता है।कि कितने भी भीड़-भाड़ हो लेकिन बस चालकों को रफ्तार में कमी नहीं होती है। ऐसा ही वाकिया अभी सोहागपुर के समीपवर्ती ग्राम लांगा बम्होरी में एक बार खाती स्पीड से चलती बस एमपी 04 पीए 2933 ने बाइक सवार युवक एवं महिला बैठी थी। टक्कर मार दी। इससे वहां काफी विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। काफी नागरिक वहां एकत्रित हो गए। इसी बीच किसी ने बस का कांच तोड़ दिया। जिला प्रशासन से नागरिकों का आग्रह है कि बल खाती एवं स्पीड से चलने वाली बसों पर अंकुश लगाएं।

अब नहीं होगी लाइट गुल होने की समस्या

प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी पहुँची 85 हजार एमवीए के पार

बैतूल। प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी कुल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी (पारेषण क्षमता) को 85,000 एमवीए के पार पहुँचा दिया है। अब मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) की कुल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी (पारेषण क्षमता) बढ़कर 85284 एमवीए की हो गई है। इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) द्वारा 400 केवी सबस्टेशन बीना में 315 एमवीए क्षमता के अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना एवं उसके सफल ऊर्जीकरण का योगदान रहा है। मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विकास तथा विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण सबस्टेशन की क्षमता में वृद्धि की गई है जो अब बढ़कर 1260 एमवीए की हो गई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का 85,000 एमवीए के आंकड़े को पार करना ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी बिजली कर्मियों, अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनकी लगन, तकनीकी दक्षता और समर्पित कार्यशैली का परिणाम है।

प्रदेश की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी पहुंची 85 हजार के पार- एमपी ट्रांसको के पास वर्तमान में कुल 85248 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी हो गई है। कंपनी के नेटवर्क में कुल 1,052 अति उच्च वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर स्थापित हैं, जिनमें 400 केवी के 41, 220 केवी के 220 तथा 132 केवी के 791 ट्रांसफार्मर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा 43,079 सर्किट किलोमीटर लंबी अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का संचालन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कंपनी के कुल 417 सबस्टेशन कार्यरत हैं, जिनमें 400 केवी के 14, 220 केवी के 88 तथा 132 केवी के 315 सबस्टेशन शामिल हैं।

अंडरवियर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे ऑटो ड्राइवर, बोले- किराया बढ़े

भोपाल के छावनी पठार में प्रदर्शन, पेट्रोल-सीएनजी बढ़ने का विरोध जताया

भोपाल (नप्र)। पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों के बाद अब टैक्सी-ऑटो चालक किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भोपाल में भी यह मांग उठ रही है। सोमवार सुबह रायसेन रोड स्थित छावनी पठार में कई ऑटो चालक इकट्ठा हुए और अंडरवियर लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ईंधन इतना महंगा हो गया है कि अंडरवियर खरीदने तक के रुपए नहीं है। इसलिए सरकार किराया बढ़ाए।

रायसेन रोड स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। ऑटो संगठन के अध्यक्ष संजू अहिरवार ने बताया, यदि सीएनजी वाला ऑटो है तो उसमें एक दिन में 500 रुपए की गैस भरवाते हैं। इसके बदले 1200 रुपए का धंधा होता है। बाकी बचे 700 रुपए में से बचत, ऑटो की किश्त भी शामिल हैं। मुश्किल से 500 रुपए की नहीं बचते हैं। इसलिए ऑटो का किराया बढ़ाने की मांग सरकार से की है।

रोजाना बचत घट रही- ऑटो चालक पुषेंद्र अहिरवार, विशाल और राजेश ने कहा कि बढ़ती महंगाई का सबसे अधिक असर मेहनतकश वर्ग पर पड़ रहा है। ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। जिससे बचत करना तो दूर परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया है।

आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई

प्रदर्शन के दौरान ऑटो चालकों ने फटे अंडरवियर दिखाकर अपनी आर्थिक स्थिति का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ऑटो की किश्त, ईंधन खर्च, वाहन रखरखाव और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते-निभाते उनकी आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। चालकों ने कहा कि किश्त भरते-भरते अंडरवियर फट गए हैं। इतनी महंगाई में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ऑटो संगठन के अध्यक्ष अहिरवार ने कहा कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ऑटो किराए में लंबे समय से कोई संशोधन नहीं किया गया। इससे हजारों ऑटो चालकों की आय प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऑटो किराए का पुनर्निर्धारण किया जाए ताकि चालक समय पर वाहन की किस्त जमा कर सकें और अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर सकें।

संक्षिप्त समाचार

रेनीपानी में बड़ी कार्रवाई: अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि वन विभाग को सौंपी

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर के सख्त निर्देश पर भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम रेनीपानी में शासकीय भूमि पर बाहर से आए परिवारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को राजस्व, वन और पर्यटन विभाग की संयुक्त टीम ने हटाकर भूमि को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। कलेक्टर के आदेश का पालन कराने में स्थानीय राजस्व अमले की भूमिका अहम रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एसडीएम प्रियंका भल्लावी, तहसीलदार राम किशोर झरबडे और नायब तहसीलदार रंजीत चौहान के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने ग्राम रेनीपानी में कार्रवाई की। यहां बाहर से आए करीब 5 परिवारों ने शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा था। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश थे कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के तुरंत बाद संरक्षण और प्रबंधन के लिए वन विभाग को सौंप दिया जाए। आदेश के तहत मौके पर ही राजस्व टीम की मौजूदगी में भूमि का हस्तांतरण वन विभाग को कर दिया गया, ताकि दोबारा कब्जा न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया कि शासकीय संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। राजस्व टीम और अन्य विभागों की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र के नागरिकों ने सराहना की है।

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 9 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल ने गुरूवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के ग्राम एहलवाड़ा, पोखरनी, पोखरनी स्थित ढाबा, वार्ड क्रमांक 1 टिमरनी उड़ा, पीलियाखाल फाइल वार्ड में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 56 पाव देशी शराब, 13 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब, 390 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुनित बाजार मूल्य 44868 रूपये है।श्री भोजने ने बताया कि अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई, कम्पोजिट मदिरा दुकान चारूवा, हरदा क्रमांक-2, छीपानेर रोड़ हरदा, रहटगांव व टेमागांव पर कलेक्टर द्वारा अधिरोपित शास्ति राशि रूपये 11 लाख 44 हजार 28 रूपये की गई थी, जो 4 जून तक जमा हो गये हैं।

कलेक्टर ने फार्मर आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने सभी राजस्व अधिकारियों को किसानों की फार्मर आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास फार्मर आईडी होना आवश्यक है। इसकी प्राथमिकता को देखते हुए जिले के सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी समय-सीमा में बनाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि फॉर्मर आईडी बनाने का कार्य अपेक्षित गंभीरता से नहीं लिया जा रहा हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों एवं पटवारियों को निर्देशित किया है कि फार्मर आईडी निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि कार्य की गति में सुधार नही लाया गया तो संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। फार्मर आईडी नहीं होने से किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है। कलेक्टर ने सभी किसानों से अपील की है कि वह फार्मर आईडी अवश्य बनवाएं।

रोजगार मेले में 218 युवक-युवतियों ने कराया पंजीयन

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशन में 6 जून को जिला पंचायत सभाकक्ष बैतूल में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं प्रदान संस्था बैतूल के संयुक्त तत्वावधान में ट्राइडेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बुधनी द्वारा जिला स्तरीय विशेष रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का उद्देश्य जिले के शिक्षित एवं रोजगार की तलाश कर रहे युवक-युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल करना था।

रोजगार मेले में जिले के विभिन्न विकासखंडों से बड़ी संख्या में युवक-युवतियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। मेले के दौरान कुल 182 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीयन कराया गया, जिनमें महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के अभ्यर्थी शामिल रहे। कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कर उनकी पात्रता के अनुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में 86 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जबकि शेष पंजीकृत अभ्यर्थियों की साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी सोमवार को पूर्ण की जाएगी।

चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। मेडिकल परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को ट्राइडेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड , बुधनी में नियुक्ति प्रदान कर कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के युवाओं को प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान में रोजगार प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होगा। रोजगार मेले के दौरान उपस्थित युवाओं को कंपनी की कार्यप्रणाली, कार्यस्थल की सुविधाओं, वेतनमान, कार्य अवधि, पद की जिम्मेदारियों एवं भविष्य में उपलब्ध होने वाले विकास के अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अभ्यर्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें रोजगार संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। रोजगार मेले के दौरान ट्राइडेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बुधनी द्वारा शीटिंग विभाग के लिए फ्रेशर अभ्यर्थियों की भर्ती की प्रक्रिया संचालित की गई। कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को लगभग 18 हजार प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जाएगा। भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई थी तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण रखी गई। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिदिन 08 घंटे की कार्य अवधि के अंतर्गत कंपनी में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे आयोजन न केवल बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान जिला परियोजना प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बैतूल श्री सतीश पवार द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने तथा रोजगार के माध्यम से अपने भविष्य को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं आजीविका मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं तथा भविष्य में भी इस प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन , बैतूल की जिला एवं विकासखंड स्तरीय टीम, प्रदान संस्था, बैतूल के अधिकारी एवं कर्मचारी, ट्राइडेंट कंपनी के प्रतिनिधिगण तथा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में युवक-युवतियां उपस्थित रहे। रोजगार मेले के सफल आयोजन में आजीविका मिशन एवं प्रदान संस्था के अधिकारियों - कर्मचारियों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत दिव्यांगों को लाभ मिले

नदियों में नालों के माध्यम से मिलने वाले ठोस अपशिष्ट को रोकने का प्रबन्धन किया जाए

■ ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य हो

हरदा (निप्र)। निरामय योजना में निःशक्तों को उपचार के लिये मिले आर्थिक सहायतास्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबों के विक्रय की शिकायतें न आएजुवेनाईल डायबिटीज के शतप्रतिशत मामलों में बच्चों को नियमित उपचार मिलेराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने जिले में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कीहरदा 5 जून 2026/ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो ने शुक्रवार को जिले में केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने कहा कि दिव्यांगजनों के लिये संचालित योजनाओं का शतप्रतिशत दिव्यांगों को लाभ मिले। जिले में नर्मदा जैसी बड़ी नदियों में नालों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट को मिलने से रोकने के लिये बेहतर प्रबन्धन किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रभावी उपाय अपनाये जाएं। उन्होने निःशक्तों को उपचार और परिवहन के लिये संचालित निरामय योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि प्रत्येक पात्र दिव्यांग को इस योजना का लाभ पहुँचाने के प्रयास किये जाएं। बैठक में कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, एसपी श्री शशांक, वनमण्डलाधिकारी श्रीमती ज्योति मुड़िया, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में श्री कानूनगो ने जिले के शासकीय केन्द्रों में संचालित आंगनवाड़ी भवनों में लगाये गये सौलर ऊर्जा संयत्रों के कार्य की सराहना की। साथ ही कहा कि इनका नियमित संधारण किया जाए। उन्होने स्कूलों में बिजली एवं पानी की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के आधार एवं समग्र आईडी में सुधार की स्थिति में तत्परता से उचित सुधार करवाने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये। बैठक में कहा गया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को निजी प्रकाशकों की किताबों के विक्रय संबंधी शिकायतें प्राप्त न हों। इस दौरान श्री कानूनगो ने बच्चों के अधिकार और किशोर न्याय प्रणाली व्यवस्था, नाबालिग गुम बालक बालिकाओं की जानकारियां वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज कराने, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, बच्चों के लिये पीएम केयर योजनाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मध्यान्ह भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की।

इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिये स्कूलों की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई। महाविद्यालय एवं स्कूली विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई। बैठक में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मोबाइल हेल्थ टीम द्वारा बच्चों की स्क्रीनिंग, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं शासकीय स्कूलों में जन्मजात विकृति, डिसीज, डिफिशिएन्सी, डेवलपमेन्ट डिले एवं विकलांगता संबंधी स्क्रीनिंग के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से श्री कानूनगो ने विस्तार से चर्चा की। जिले में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों की स्थिति पर भी श्री कानूनगो द्वारा संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली गई।

एकीकृत खेती और मृदा परीक्षण से बदली तकदीर

किसान मदन ठाकुर ने तीन गुना बढ़ाई आय

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के कुरवाई विकासखंड अंतर्गत ग्राम दांगी कुम्हारियां के प्रगतिशील किसान श्री मदन ठाकुर ने आधुनिक कृषि तकनीकों, मृदा परीक्षण एवं एकीकृत खेती को अपनाकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया है। उनकी सफलता आज क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।

श्री मदन ठाकुर, पिता श्री कुंवर सिंह दांगी, बी.कॉम स्नातक हैं तथा लगभग 10 हेक्टेयर सिंचित भूमि पर खेती करते हैं। शिक्षा और जागरूकता के बल पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में नवाचार अपनाते हुए अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उनका मानना है कि खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी जानकारी सफलता की कुंजी है।

मृदा परीक्षण से बढ़ा उत्पादन, घटी लागत: मदन ठाकुर बताते हैं कि पहले वे अपनी समझ के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करते थे, जिससे लागत अधिक आती थी और अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता था। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में मृदा परीक्षण कराने के बाद उन्हें अपनी भूमि की पोषक तत्व आवश्यकताओं की सही जानकारी मिली। इसके आधार पर उन्होंने अनुशंसित मात्रा में ही उर्वरकों का उपयोग शुरू किया। इस बदलाव का सकारात्मक परिणाम सामने आया। खेती की लागत में कमी आई और उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जहां पहले गेहूं की फसल से अधिकतम 8 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन प्राप्त होता था, वहीं मृदा परीक्षण आधारित पोषण प्रबंधन अपनाने के बाद उन्होंने 15 क्विंटल प्रति बीघा तक उत्पादन प्राप्त किया।

तीन गुना तक बढ़ी वार्षिक आय

वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, मृदा परीक्षण तथा एकीकृत खेती के सकारात्मक परिणाम उनकी आय में स्पष्ट दिखाई देते हैं। श्री ठाकुर बताते हैं कि पहले रबी एवं खरीफ सीजन की फसलों से उन्हें वर्षभर में लगभग 8 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त होता था। वर्तमान में यही लाभ बढ़कर लगभग 25 लाख रुपये वार्षिक तक पहुंच गया है। उनकी इस उपलब्धि ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाएं और विभागीय योजनाओं का लाभ लें तो खेती को अत्यधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

विभागीय योजनाओं से मिला संबल

श्री मदन ठाकुर नियमित रूप से कृषि विभाग, कुरवाई के संपर्क में रहते हैं तथा समय-समय पर संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाते हैं। कृषि विभाग के अलावा वे उद्यानिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। वे बताते हैं कि भविष्य में अपनी आधी भूमि पर प्राकृतिक खेती को विस्तार देने की योजना है। साथ ही वे ऐसी फसलों का चयन करना चाहते हैं जो क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हों, कम लागत में अधिक उत्पादन दें तथा किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करें।

प्रेरणादायक संदेश

श्री मदन ठाकुर की सफलता इस बात का उदाहरण है कि वैज्ञानिक कृषि तकनीकों, मृदा परीक्षण, प्राकृतिक खेती और विभागीय योजनाओं के समुचित उपयोग से किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। उनकी उपलब्धियां क्षेत्र के अन्य किसानों को भी आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता एवं पौधारोपण अभियान

बैतूल (निप्र)। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न गतिविधियों के क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोप किया गया। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए परिसर में सघन साफ-सफाई अभियान चलाया तथा 50 पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना , स्वच्छता को प्रोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। अभियान के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने परिसर की साफ-सफाई कर स्वच्छ वातावरण बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कलेक्ट्रेट परिसर में श्रम, कोषालय, खाद्य, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान परिसर को स्वच्छ एवं हरित बनाने के उद्देश्य से पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं नगर पालिका की टीम उपस्थित रही।

सिरोंज पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने रचा इतिहास, तीनों इंजीनियरिंग ब्रांचों में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट

विदिशा (निप्र)। सिरोंज पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने वर्ष 2026 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तीनों शाखाओं में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। विद्यार्थियों की इस सफलता ने न केवल महाविद्यालय का गौरव बढ़ाया है, बल्कि क्षेत्र के तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए भी एक नया मानक स्थापित किया है। महाविद्यालय की प्राचार्य भावना दांगी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन तथा संस्थान के रोजगारोन्मुखी शैक्षणिक वातावरण के कारण यह सफलता संभव हो सकी है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। प्लेसमेंट अधिकारी रागिनी अरजरिया ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस वर्ष विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आयोजित ओपन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सुब्रोस लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन शाखा से छोटू नायक एवं ऋतिक कुशवाह तथा सिविल शाखा से हुकुम सिंह कुशवाह एवं मनोज कुशवाह का चयन हुआ।

इसी प्रकार सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन शाखा के लखन सिंह, सोनम अहिरवार एवं उर्मिला कुशवाह का चयन किया गया। वहीं कृष्णा मारुति लिमिटेड में मनोज कुशवाह, हुकुम सिंह एवं निखिल बैरागी को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ।

"पेड़ पौधे लगाएंगे हम, पृथ्वी को बचाएंगे हम" संकल्प के साथ

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर हरदा, डॉ. भीमराव अंबेडकर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदा के बालिका छात्रावास, आंगनवाड़ी केन्द्र क्रं. 68 वार्ड क्रं. 17 हरदा में वृक्षारोपण सह विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री निसार अहमद, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कपिल वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रशेखर राठौर, न्यायाधीश श्री एस.के. भदकारिया, न्यायाधीश श्री प्रेमदीप शाह, न्यायाधीश श्रीमती चेतना रूसिया, जिला अधिवक्ता संघ, हरदा के अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा, सचिव श्री शैलेन्द्र जोशी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण हरदा ने विभिन्न प्रकार के फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया। कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद रघुवंशी ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण को संरक्षित करने में सहायक है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं और पक्षकारों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने संकल्प लिया कि वे न केवल अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, बल्कि उनके संरक्षण और देखभाल का भी पूरा ध्यान रखेंगे।

कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन हेतु एक सामूहिक प्रतिज्ञा ली। वृक्षारोपण कार्यक्रम के सफल आयोजन में न्यायालय प्रशासन, अधिवक्ता संघ, पैरालीगल वॉलेंटियर और पक्षकारों का सहयोग सराहनीय रहा। शिविरों में उपस्थित न्यायाधीश व सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थितजनों को बताया गया कि धरती पर जीवन का आधार पर्यावरण है। स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, हरे-भरे जंगल और जैव विविधता मानव अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण को गंभीर संकट की ओर धकेल रहा है।

विश्व पर्यावरण दिवस: जन अभियान परिषद ने जिले के 223 ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियां की आयोजित

बैतूल (निप्र)। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के निर्देशन एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिलेभर में पौधारोपण, वृक्ष पूजन, जल संगोष्ठी, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, मेंटर्स तथा ग्रामीणजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। जिले के विभिन्न विकासखंडों में कुल 110 ग्रामों में 879 पौधों का रोपण किया गया। विकासखंड बैतूल के 22 ग्रामों में 92 पौधे , आमला के 7 ग्रामों में 118 पौधे, आठनेर के 8 ग्रामों में 120 पौधे, भीमपुर के 9 ग्रामों में 145 पौधे, चिचोली के 8 ग्रामों में 120 पौधे, घोड़ाडोंगरी के 3 ग्रामों में 31 पौधे, शाहपुर क्षेत्र के 5 ग्रामों में 65 पौधे, प्रभातपट्टन के 31 ग्रामों में 36 पौधे, भैंसदेही के 13 ग्रामों में 117 पौधे तथा मुलताई के 7 ग्रामों में 35 पौधों का रोपण किया गया। पौधरोपण के साथ ही ग्रामों में वृक्ष पूजन, जल संरक्षण संगोष्ठी, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त ग्राम अभियान, पर्यावरण संगोष्ठी एवं जनजागरूकता की अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, स्वच्छता तथा जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। विकासखंड बैतूल में जय गुरुदेव उत्थान संस्था, नगर विकास प्रस्फुटन समिति, अंश सेवा समिति एवं विभिन्न प्रस्फुटन समितियों द्वारा पौधारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। भीमपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी एवं शाहपुर क्षेत्र में नवांकुर संस्थाओं द्वारा पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई।

वीआईपी क्षेत्र में पहली बार जल संकट

लीजिए साहब! राजधानी का वो अति-विशिष्ट 'वीआईपी इलाका' भी आखिरकार आम जनता की कतार में आकर खड़ा हो गया, जो अमूमन हर साल जल संकट के दंश से पूरी तरह अछूता और महफूज रहता था। इस बार कोलार क्षेत्र में कोलार की पाइप लाइन फूटने से तीन दिन नए शहर का आधा इलाका जल संकट से हाहाकार कर बैठा जिसमें वीआईपी क्षेत्र को भी हिलाकर रख दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी के उसी 'चार इमली' इलाके की, जहां राज्य सरकार के मंत्रियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के आला अधिकारियों के आलीशान बंगले चमचमाते हैं। इस वीआईपी जोन में भी ऐसा गंभीर जल संकट देखा गया कि सत्ता के गलियारों में हड़कंप मच गया। आलम यह था कि एसी कमरों में बैठकर नीतियां बनाने वाले अखिल भारतीय सेवा के बड़े-बड़े साहब, भोपाल नगर निगम के अदने से कर्मचारियों तक को लगातार पानी की निर्बाध सप्लाई के लिए फोन घुमा रहे थे और उनसे एक-एक पानी के टैंकर के लिए बाकायदा गुजारिश कर रहे थे। व्यवस्थाओं की पोल तो तब और खुल गई, जब एक लाचार आईएएस अधिकारी को अपने बंगले में पानी का टैंकर भिजवाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक गुहार लगानी पड़ी। तब कहीं जाकर वहां तैनात एक अन्य रसूखदार आईएएस अधिकारी ने नगर निगम के संबंधित इंजीनियर को कड़क लहजे में निर्देश दिया, तब जाकर साहब के बंगले पर टेंकर से पानी सप्लाई हो सका। जब 'अपनों' पर बनी, तब पता चला कि पानी का दर्द क्या होता है!

मोहन का मंत्रालय
आशीष चौधरी

यहां भी खेत रहे पूर्व मंत्री

ऐसा लगता है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी उनका नाम सुर्खियों में था, अब राज्यसभा चुनाव में उनका टिकट मिलने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही थी। तो उन्होंने दिल्ली जाकर जमकर लॉबिंग भी की। लेकिन जब पार्टी ने भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा की, तो इस बार भी उनके हाथ लगी वही पुरानी असफलताएं! वैसे, माननीय पूर्व मंत्री जी ने अपनी राजनीतिक कामयाबी के लिए पिछले दिनों एक बहुत बड़ा महायज्ञ भी कराया था, जिसमें अपनी हाजिरी लगाने कई केंद्रीय मंत्री और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे थे। इस भारी-भरकम कर्मकांड के पीछे जाहिर तौर पर उनकी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छिपी थी। लेकिन जनता को यह बता देना बेहद जरूरी है कि पूर्व मंत्री जी पिछले विधानसभा चुनाव में बकायदा मंत्री पद की शोभा बढ़ा रहे थे, और कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक को सरेआम, खुलेआम अपशब्द कहने के अपने 'अद्भुत हुनर' के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो रहे थे।

भय के लिए भाजपा ने उतारा उम्मीदवार

भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरी सीट के लिए महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर चुनावी रोमांच पैदा कर दिया है। राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के लिए भाजपा को कांग्रेस के कम से कम 8 विधायकों तोड़फोड़ करना है जो कि फिलहाल की स्थिति में असंभव लगता है लेकिन भाजपा के लिए कुछ भी संभव नहीं है। बस भाजपा की इस रणनीति ने कांग्रेस में भय पैदा कर दिया है। भाजपा ने तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार उतार कर रणनीति के तहत कांग्रेस भयभीत है। कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा की उम्मीदवार है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा की बैठक में संगठन ने यह कहकर विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश दिया है और कहां है कि वह अपने स्तर से अगर कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी कर सकते हैं तो इसका भी प्रयास करें। इधर कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना या कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी में है।

ट्वीट करना पड़ा भारी 37 साल की निष्ठा पर

करीब 37 वर्षों तक कांग्रेस की 'सिंघम' निष्ठा निभाने वाले नरेश ज्ञानचंदानी ने आहत होकर पार्टी को ऐसा 'इस्तीफा पत्र' थमाया है। जिसने संगठन की अंदरूनी सियासत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। मोतीलाल वोरा की उंगली थामकर राजनीति में आए और दिग्विजय सिंह व कमलनाथ के मार्गदर्शन में भाजपा के पारंपरिक 'सिंधी वोट बैंक' में सेंध लगाने वाले इस कद्दावर नेता को मलाल है कि शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किए गए महज एक ट्वीट को पार्टी ने गुनाह मान लिया। ट्वीट में राज्यसभा के लिए चयन से जुड़ा था। आहत होकर अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल-प्रियंका तक को इस्तीफे की प्रति भेजकर जीतू पटवारी के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर जारी 'अनुशासन' और सांगठनिक मजबूती के दावों पर एक ऐसा मौन कटाक्ष कर दिया है, जिस पर फिलहाल पूरी पार्टी सांप सूंघ जाने जैसी खामोशी अख्तियार किए बैठी है।

कंटेनर में घुसा डंपर, केबिन बना लोहे का पिंजरा

शिवपुरी (नप्र)। एक रूह कंपा देने वाला हादसा शिवपुरी जिले के अमोला थाना क्षेत्र के सलैया गांव के पास हुआ। दरअसल, शिवपुरी से झांसी की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने आगे चल रहे कंटेनर को पीछे से ऐसी टक्कर मारी कि डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। इस भीषण भिड़ंत में ललितपुर का रहने वाला हल्के यादव डंपर के केबिन के भीतर ही बुरी तरह फंस गया। केबिन लोहे के जाल की तरह उसके शरीर पर कस चुका था। घटना की भनक लगते ही हाईवे चौकी के आरक्षक नागेंद्र जाट और संजीव श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, लेकिन कबाड़ बन चुके केबिन से घायल को हाथ से निकालना नामुमकिन था।

एक ही पट्टी पर बैक-टू-बैक दो हादसों से थमा फोरलेन

दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इस डंपर-कंटेनर की भिड़ंत से कुछ घंटे पहले ही इसी फोरलेन पर एक और कांड हो चुका था। गलत दिशा से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही कार को चीर दिया था। अमोला थाना पुलिस अभी उस पहली दुर्घटना की स्थिति को संभाल ही रही थी, गाड़ियां रास्ते से हटवाई ही जा रही थीं कि दूसरी तरफ इस डंपर ने मौत की रफ्तार से कंटेनर को ठोक दिया। इन दो लगातार हादसों के चलते फोरलेन की दोनों पट्टियों पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया और सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रहीं।

राज्यसभा सदस्य के लिए भाजपा नेता महेश केवट ने नामांकन दाखिल किया

हम इस चुनाव में जीत के लिए संकल्पित हैं : सीएम मोहन यादव

फोटो : प्रवीण वाजपेई

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान सीएम मोहन यादव समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता वहां मौजूद रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस चुनाव में जीत के लिए हम संकल्पित हैं। केवट के नाम का चयन भारतीय जनता पार्टी के सब वर्गों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

महेश केवट हैं तीसरे प्रत्याशी- नामांकन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा चुनाव में तीसरे प्रत्याशी के रूप में महेश केवट का चयन किया है। उन्होंने आज नामांकन फॉर्म जमा कराया है। हम इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि हम तीनों राज्यसभा की सीटों पर निर्वाचित होकर रहेंगे।

बाल्यकाल से रहे हैं स्वयं सेवक- सीएम यादव ने कहा कि महेश केवट बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद-युवा मोर्चा में रहे हैं। संघ में कई उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। आज भगवान राम का आशीर्वाद एक बार फिर निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट को मिल रहा है। हम सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हैं।

जब-जब जो कहा, तब-तब वो किया- उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। मुझे इस बात का आनंद है कि जिस वर्ग का लोकसभा-विधानसभा में कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, उस वर्ग के प्रतिनिधि को सीधे उच्च सदन में अवसर मिल रहा है। यह निर्णय हमारी पार्टी की सब वर्गों के कल्याण की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

गौरतलब है कि महेश केवट मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के रहने वाले हैं। वह मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। संघ और संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं। इसलिए उन्हें यह मौका मिला है।

विजयवर्गीय का दावा- बीजेपी के साथ रहेंगी निर्मला सप्रे

कांग्रेस की राज्यसभा कैंडिडेट मीनाक्षी बोलीं- हम एकजुट; दिग्विजय समर्थक ज्ञानचंदानी का पार्टी से इस्तीफा

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया- बीना विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी के साथ रहेंगी। इससे पहले, कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विधायकों के साथ

विधानसभा पहुंचीं। यहां राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया। नटराजन ने कहा- हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे।दूसरी तरफ, भोपाल की हुजूर सीट से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके नरेश ज्ञानचंदानी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वे मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं।

बीना विधायक सीएम हाउस पहुंचीं

एक अन्य घटनाक्रम में बीना विधायक निर्मला सप्रे आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने सीएम हाउस गई थीं। हालांकि, यहां क्या चर्चा हुई, इसका पता नहीं चल सका है।

गुना में दूषित जल का कहर

डेढ़ दर्जन से अधिक बच्चे बीमार, पीलिया और हेपेटाइटिस ए से पीड़ित

गुना (नप्र)। शहर के बूढ़े बालाजी, पुरानी छावनी सहित कई रिहायशी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही दूषित पानी की सप्लाई अब मासूमों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में बीते तीन-चार दिनों के भीतर उल्टी-दस्त और तेज पेट दर्द से पीड़ित डेढ़ दर्जन से अधिक बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है।

पीलिया और हेपेटाइटिस ए जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित- डॉक्टरों शुरुआती जांच में कई बच्चे पीलियाऔर हेपेटाइटिस ए जैसी खतरनाक बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, ये दोनों ही बीमारियां सीधे तौर पर प्रदूषित जल और संक्रमित भोजन के सेवन से फैलती हैं। अस्पताल में भर्ती ज्यादातर बच्चे बूढ़े बालाजी, पुरानी छावनी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जैसे घने बसे क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

घरों में आ रहा बदबूदार पानी- इन क्षेत्रों के नागरिकों का आरोप है कि पिछले 15 दिनों से उनके घरों में नलों के जरिए बेहद बदबूदार और गंदा पानी भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे लगातार बीमार हो रहे। शुरुआत में परिजनों ने निजी डॉक्टरों से प्राथमिक उपचार कराया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल लाना पड़ा। जब अचानक बड़ी संख्या में पीड़ित बच्चे अस्पताल पहुंचे तो प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

बड़ी संख्या में बच्चे पहुंच रहे अस्पताल- चौंकाने वाली बात यह है कि तीन दिनों से एक ही इलाके से इतनी बड़ी संख्या में बीमार बच्चे जिला चिकित्सालय पहुंच रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। न तो प्रशासन को समय रहते इस प्रकोप की सूचना दी गई और न ही अस्पताल में कोई अलर्ट जारी किया गया। रविवार को जब यह पूरा मामला सार्वजनिक रूप से गरमाया, तब भी अस्पताल के शिशु वार्ड में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात नहीं था। इमरजेंसी ड्यूटी संभाल रहे मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. धाकड़ ही अकेले इन बच्चों का इलाज करते नजर आए।

रविवार को सामने आई जानकारी- दरअसल, बूढ़े बालाजी क्षेत्र के पार्षद पति लालाराम लोधा रविवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने किसी परिचित के घर बीमार बच्चे को देखने गए थे, जहां उन्हें पता चला कि पूरे वार्ड में दर्जनों बच्चे इसी तरह उल्टियों और दस्त से तड़प रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग को दी। शाम होते-होते भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार भी अपनी टीम के साथ जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड पहुंचे।

20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं; मानसून से पहले कोटे से 65 प्रतिशत ज्यादा बारिश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अभी नहीं हुई है, लेकिन बारिश का दौर जारी है। जून में अब तक कोटे की 65 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें विदिशा, अशोकनगर, सागर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और दमोह शामिल हैं। प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है, जबकि जून का सामान्य औसत 8.3 मिमी होता है। भोपाल, आगर-मालवा और शाजापुर में करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि नीमच में ढाई इंच बारिश दर्ज की गई है।

मानसून की एंट्री की संभावना

मानसून रविवार को महाराष्ट्र पहुंच गया है। अनुमान है कि यह मध्य प्रदेश में 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। राज्य में इसकी तय तारीख 15 जून है, जबकि पिछले साल यह 16 जून को पहुंचा था।

अब तक इन जिलों में 1 इंच से ज्यादा बारिश

सतना, सीधी, आगर-मालवा, भोपाल, बुरहानपुर, हरदा, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर में 1 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो मानसूनी बारिश 1 जून से ही रिकॉर्ड की जाती है, जो 30 सितंबर तक चलती है। इस दौरान होने वाली वाली मानसूनी बारिश कहलाती है। वर्तमान में प्रदेश में प्री-मानसूनी एक्टिविटी चल रही है।

भोपाल पुलिस का मानवीय चेहरा, सीपीआर देकर बचाई जान

पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अचानक आया था युवक को हार्ट अटैक

भोपाल (नप्र)। भोपाल पुलिस के जवानों ने एक बार फिर मानवता और कर्तव्य की मिसाल पेश की। पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में अचानक एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। समय पर मिली मदद से करीब पांच मिनट के भीतर उसकी हालत संभली और उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार पुलिस कमिश्नर कार्यालय में देवेंद्र सक्सेना अचानक गिर पड़े। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को समझते हुए तुरंत मदद शुरू की। उन्हें हार्ट अटैक की आशंका हुई तो आरक्षक मुकेश साहू और रंजीत रघुवंशी ने बिना समय गंवाए सीपीआर देना शुरू किया।

आरआई ने अपने वाहन से हॉस्पिटल पहुंचाया- पुलिसकर्मियों की तत्परता से देवेंद्र की सांस और धड़कन को सामान्य करने का प्रयास किया गया। कुछ ही देर में उनकी स्थिति में सुधार दिखाई देने लगा। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।

आरआई जयसिंह तोमर ने अपने वाहन से देवेंद्र सक्सेना को अनंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टरों ने समय पर अस्पताल पहुंचने को बेहद महत्वपूर्ण बताया।

जमीन विवाद को लेकर 12 राउंड फायरिंग

प्लॉट पर सफाई करने आए मजदूर और ठेकेदार पर गार्डों ने चलाई गोलियां

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र के सुरेंद्र लैंडमार्क इलाके में शनिवार देर रात जमीन विवाद के चलते फायरिंग से दहशत फैल गई। शालीमार कॉलोनी के पास विवादित जमीन पर साफ-सफाई करने पहुंचे ठेकेदार और मजदूरों पर दो सिक्योरिटी गार्डों ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूकों से करीब 12 राउंड फायर कर दिए। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार दोनों गार्ड फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को काबू में किया और उनकी बंदूकें जब्त कर लीं। मौके से पुलिस ने करीब 250 मीटर क्षेत्र में 12 बोर कारतूस के 12 खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शालीमार एन्क्लेव के पास करीब पांच एकड़ जमीन को लेकर मीरचंदानी-परियानी परिवार और अजय नागर के बीच विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में लंबित है। शनिवार रात अजय नागर के ठेकेदार अंकित कुमार मजदूरों के साथ जमीन की सफाई कराने पहुंचे थे।

कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बनी विशेष समन्वय समिति, ग्रेडिंग के आधार पर तय होंगे अस्पताल : शिवराज

मरीजों से फोन पर संपर्क कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करेंगी समिति

भोपाल/विदिशा (नप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विदिशा मेडिकल कॉलेज में 6 और 7 जून को दो दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई और एम्स भोपाल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कैंसर की जांच की गई। जिसमें 586 कैंसर मरीज व 254 संदिग्ध मरीज शामिल हैं। इन दो दिनों में विदिशा संसदीय क्षेत्र सहित प्रदेश के दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में मरीज जांच के लिए पहुंचे। जांच के दौरान कई मरीज कैंसर पॉजीटिव पाए गए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कैंसर पॉजीटिव पाए गए किसी भी मरीज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी मरीजों के उपचार की व्यवस्थित योजना बनाई जाएगी और उन्हें उचित अस्पताल में इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल जांच कराना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है।

शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि, कैंसर मरीजों के इलाज के लिए एक औपचारिक समन्वय समिति गठित की गई है। इस समिति में तोरण सिंह दांगी, डॉ. राजेन्द्र राय और डॉ. एम.के. सोनी सहित अन्य जिम्मेदार सदस्य शामिल हैं। जिला प्रशासन, विदिशा मेडिकल कॉलेज और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से यह समिति मरीजों की ग्रेडिंग करेगी और यह तय करेगी कि किस मरीज का इलाज किस अस्पताल में किया जाना है। उन्होंने कहा कि समिति संबंधित अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित कर उपचार की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेगी। मरीजों की बीमारी की स्थिति के अनुसार उन्हें उपयुक्त संस्थान में भेजा जाएगा और उनके इलाज की निरंतर निगरानी भी की जाएगी।

मरीजों से फोन पर संपर्क कर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करेंगी समिति

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, जितने भी मरीज कैंसर पॉजीटिव पाए गए हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। समिति हर मरीज का परीक्षण और चिकित्सकीय आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेकर उन्हें खुद सूचित करेगी कि किस अस्पताल में जाकर उपचार कराना है। सभी मरीजों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और उपचार प्रक्रिया के दौरान आवश्यक समन्वय भी किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार, चिकित्सकीय संस्थान और प्रशासन मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मरीज को इलाज के लिए भटकना न पड़े और समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।